प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए विशेष पंजीकरण अभियान 15 अगस्त, 2025 तक

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

लोकशक्ति

लोकसभा में अभिषेक बनर्जी होंगे TMC के नए नेता, सुदीप

RNI Regn. No.7789/1964 | वर्ष-61 > अंक - 223 | रायपुर | मंगलवार 05 अगस्त 2025 विक्रम संवत 2082 | पृष्ठ 8 > मूल्य : 2 रू. | डाक पंजीयन : C.G./RYP DN/71/2023-25

राहुल गांधी के द्वारा सेना पर दिये गये विवादित बयान को लेकर सुप्रीम कोर्ट की नसीहत

सच्चा भारतीय सेना पर ऐसी टिप्पणी नहीं करेगा : राहुल गांधी को फटकार

नई दिल्ली एजेंसी।

भारतीय सेना पर कथित टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी के खिलाफमानहानि का मामला दर्ज किया गया था. अब इस मामले में कांग्रेस नेता को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने लखनऊ ट्रायल कोर्ट के समन पर रोक लगाई है. कोर्ट ने मामले में नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. राहुल गांधी ने दिसंबर 2022 में अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भारतीय सेना पर कथित टिप्पणी की थी.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आखिर आपने यह संसद में क्यों नहीं कहा और सोशल मीडिया पर क्यों कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आप सच्चे भारतीय है तो आपको यह नहीं कहना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपके पास भले ही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन यह क्यों कहा. आप एक जिम्मेदार नेता हैं. वरिष्ठ अधिवक्ता सिंघवी ने कहा कि अगर विपक्ष के नेता के तौर पर वह यह सब नहीं कह सकते, तो इसका क्या नतीजा निकलेगा?

कोई सच्चा भारतीय ऐसा नहीं कहेगा - जस्टिस दत्ता ने कहा कि आपको कैसे पता चला कि चीन ने 2000 वर्ग किलोमीटर कब कब्जा कर लिया? विश्वसनीय जानकारी क्या है? एक सच्चा भारतीय ऐसा नहीं कहेगा. जब सीमा पार कोई विवाद हो तो क्या आप ये सब कह सकते हैं? आप संसद में सवाल क्यों नहीं पूछ सकते? इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सिंघवी से कहा कि आपने हाईकोर्ट में दूसरी लाइन ली थी. सिंघवी ने कहा कि एक तरीका है कि आप विपक्ष के नेता बन जाएं और सब को बदनाम करें. लेकिन यहां ऐसा नहीं था. सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया. रोक लगा दी. साथ ही कोर्ट ने तीन सप्ताह में जवाब मांगा. मई में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लखनऊ की एमपी-एमएलए अदालत द्वारा पारित समन आदेश को चुनौती देने वाली गांधी की याचिका को खारिज कर दिया था.

राहुल गांधी ने यह बयान दिया था

राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया गया था क्योंकि उन्होंने सेना को लेकर टिप्पणी की थी. राहुल गांधी ने कहा था कि चीनी सैनिक अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सैनिकों की पिटाई कर रहे हैं. यह टिप्पणी 2022 में राजस्थान में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान की गई थी. कांग्रेस नेता ने कहा था, लोग भारत जोड़ो यात्रा, अशोक गहलोत और सचिन पायलट वगैरह के बारे में इधर-उधर पूछेंगे. लेकिन वे चीन के 2000 वर्ग किलोमीटर भारतीय जमीन पर कब्जा करने, 20 भारतीय सैनिकों को मारने और अरुणाचल प्रदेश में हमारे सैनिकों की पिटाई के बारे में एक भी सवाल नहीं पूछेंगे.

भारतीय प्रेस उनसे इस बारे में एक सवाल भी नहीं पूछता. उनके इसी बयान को लेकर मामला दर्ज किया गया था. उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया गया था और एक निचली अदालत ने उन्हें समन जारी किया था. इसके बाद उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कार्यवाही और समन रद्द करने की मांग की।

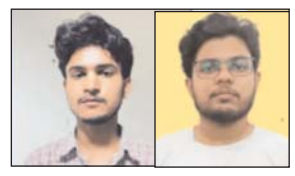

जिहाद की मदद से गजवा-ए-हिन्द करना चाहते थे युवक, पाकिस्तानियों से संपर्क में थे, यूपी ATS ने धर दबोचा

एजेंसी उत्तर प्रदेश के आतंकवाद निरोधक दस्ते ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भारत के खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र रचने और देश में सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने का मंसूबा रखने वाले दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। यूपी एटीएस द्वारा देश विरोधी तत्वों पर सतर्क निगरानी रखी जा रही थी इसी क्रम मे ज्ञात हुआ कि एक व्हाट्सएप ग्रुप Reviving Islam" है, जिसके 3 एडमिन सहित लगभग 400 पाकिस्तानी सदस्य हैं। इस ग्रुप मे एक नंबर उत्तर प्रदेश का भी जुड़ा है। पाकिस्तानी व्यक्तियो के संपर्क मे था युवक - जानकारी प्राप्त हुई कि इस मोबाइल नंबर का धारक अमरोहा का अजमल अली है। वह विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से राष्ट्रविरोधी व गैर मुस्लिम धर्म के व्यक्तियों के प्रति कट्टरपंथी विचारधारा को प्रसारित प्रचारित कर रहा है। संदिग्ध उपरोक्त को पूछताछ हेत एटीएस मुख्यालय पर बुलाया गया था।

झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का निधन, प्रधानमंत्री मोदी ने जताया दुख

एजेंसी रांची,

झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का सोमवार को 81 साल की उम्र में निधन हो गया। वह पिछले कुछ दिनों से दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) के संस्थापक सोरेन को 19 जुलाई को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनको किडनी संबंधी परेशानी थी। कुछ दिन पहले उनको वेंटीलेटर पर रखा गया था। उन्होंने सोमवार सुबह 8:56 बजे दम तोड़ा। उनके पुत्र और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली में हैं। अस्पताल के नेफ्रोलॉजी विभाग के अध्यक्ष डॉ एके भल्ला ने बताया कि सोरेन की बाईपास सर्जरी अधिक उम्र में हुई थी, जिससे रिकवरी में समय लग रहा था। उन्होंने बताया कि उनको फेफड़े और किडनी संबंधी बीमारियों के अलावा डायबिटीज भी थी और हाल में उन्हें ब्रेन स्ट्रोक भी आया था। ब्रेन स्ट्रोक के बाद उनके बाएं शरीर में पैरालिसिस की शिकायत थी। उनके बेटे हेमंत और बहु कल्पना सोरेन एक हफ्ते से दिल्ली में थे। पिता के निधन पर मुख्यमंत्री हेमंत ने एक्स पर लिखा, आदरणीय दिशोम गुरुजी हम सभी को छोड़कर चले गए हैं। आज मैं शून्य हो गया हूं...। शिबू सोरेन के निधन की सूचना पर पूरे झारखंड में शोक की लहर है।

यूपी के 17 जिले बाढ़ से प्रभावित, योगी के निर्देश के बाद हरकत में आए अधिकारी

एजेंसी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत कार्यों में तेजी लाने, पीड़ितों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के निर्देश के बाद अतिसंवेदनशील और संवेदनशील जिलों के अधिकारी हरकत में आ गए हैं। सीएम योगी के निर्देश के बाद अधिकारी अपने जिलों में बाढ़ की स्थितियों पर लगातार नजर बनाए रखे हैं। इसके साथ ही राहत कार्यों के लिए एनडीआरएफ एसडीआरएफ और पीएसी की टीमें भी मुस्तैदी से लोगों को राहत देने में लगी हुई हैं। बाढ़ के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए प्रदेश के 57 जिलों में एनडीआरएफ की 14, एसडीआरएफ की 15 और पीएसी की 48 टीमों को तैनात किया गया है।

बाढ़ से प्रभावित एक लाख से ज्यादा लोगों को दी गई राहत राहत आयुक्त भानु चंद्र गोस्वामी ने बताया कि वर्तमान में प्रदेश के 17 जिलों की 40 तहसीलें और 694 गांव बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। इन इलाकों में बाढ़ से 1,16,403 लोग प्रभावित हैं।

संसद में गतिरोध जारी, हंगामे के बाद लोकसभा की कार्यवाही स्थगित

एजेंसी नई दिल्ली :

संसद के मानसून सत्र में सरकार और विपक्ष के बीच तनाव बना हुआ है. खासकर बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के मुद्दे पर गतिरोध जारी है. विपक्ष, विशेष रूप से इंडिया ब्लॉक इस मुद्दे पर संसद में चर्चा की मांग कर रहा है. लेकिन, सरकार ने अब तक इस पर सहमति नहीं जताई है.

लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष से सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने की अपील की है. बिरला ने कहा कि जनता ने सांसदों को महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा के लिए चुना है, न कि हंगामे के लिए. उन्होंने विपक्ष से नारेबाजी और तख्तियां दिखाने के बजाय सार्थक चर्चा में हिस्सा लेने को कहा. सोमवार को

लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने विपक्षी सांसदों से मुलाकात भी की. सूत्रों की मानें तो विपक्ष ने SIR पर चर्चा करवाने की मांग की. जिसपर स्पीकर ने संवैधानिक बाध्यता बताते हुए मना कर दिया. सूत्रों की माने तो सरकार इलेक्टोरल रिफार्म्स पर चर्चा करवाने को राजी हैं मगर SIR पर नहीं. सरकार ने फैसला स्पीकर पर छोड़ दिया है. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सोमवार, 4 अगस्त को संसद के मानसून सत्र के दौरान कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ बातचीत करते हुए. अब मंगलवार से संसद के सुचारू रूप से चलने की उम्मीद की जा रही है. लेकिन एसआईआर पर चर्चा की संभावना कम दिख रही है. विपक्ष की मांगें पूरी न होने पर हंगामा जारी रह सकता है. सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम आतंकी हमले जैसे मुद्दों पर चर्चा को प्राथमिकता दी मगर चुनाव आयोग के मुद्दे कर सरकार चर्चा नहीं करवाने के मूड में है. बता दें कि 21 जुलाई को शुरू हुए मानसून सत्र के दौरान दोनों सदनों में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा को छोड़कर, बार-बार स्थगित होने के कारण बहुत कम कामकाज हुआ है. इस सूरत में एक बार फिर बगैर विपक्ष के ही बिल पारित करवाए जा सकते हैं।

भारत-पाक सीमा पर 2.50 करोड़ की हेरोइन बरामद

एजेंसी

श्रीगंगानगर, जिले के दौलतपुरा के समीपवर्ती संगतपुरा गांव में भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास एक खेत से 522 ग्राम हेरोइन बरामद की गई. बीएसएफ और मटीलीराठान पुलिस के संयुक्त अभियान में इस हेरोइन की कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में करीब 2.50 करोड़ रुपए आंकी गई है. हेरोइन पीले रंग के पैकेट में बंद थी, जिस पर कुड़ी बनी थी और छोटे अक्षरों में कुछ लिखा हुआ था. अधिकारियों का मानना है कि यह पैकेट संभवतः पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए गिराया गया. घटना का खुलासा तब हुआ जब स्थानीय किसान हरकिर्तन सिंह मान, पुत्र जसविंद्र सिंह मान, अपनी नरमे की फसल में पानी लगा रहे थे।

संदेशखाली हत्याकांड मामले में शाहजहां की परेशानी बढ़ी

हाईकोर्ट ने आरोपी के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश को बरकरार रखा

एजेंसी

कोलकाता कलकत्ता हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने आज राज्य के उत्तर 24 परगना जिले के संदेशखाली में 2019 में तीन भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) जांच पर उसी अदालत की एकल-न्यायाधीश पीठ के पहले के आदेश को बरकरार रखा। इस मामले में मुख्य आरोपियों में से एक तृणमूल कांग्रेस से निलंबित नेता शेख शाहजहां है। वह जनवरी 2024 में अपने आवास के सामने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) के कर्मियों पर हमले के मामले में भी मुख्य आरोपी हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति जय सेनगुप्ता की एकल पीठ ने 30 जून को इस मामले में सीबीआई जांच का आदेश दिया था। इसके बाद, शाहजहां ने एकल पीठ के आदेश के खिलाफ कलकत्ता हाईकोर्ट की खंडपीठ का दरवाजा खटखटाया। शाहजहां पर पश्चिम बंगाल में करोड़ों रुपए के राशन वितरण मामले में संलिप्तता, महिलाओं का यौन उत्पीड़न, और संदेशखाली में अवैध रूप से जमीन हड़पने सहित अन्य आरोप भी हैं। वर्तमान में वह न्यायिक हिरासत में है।यह मामला आज न्यायमूर्ति देबांशु बसाक और न्यायमूर्ति प्रसेनजीत बिस्वास की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया। सुनवाई के अंत में उक्त पीठ ने शाहजहां की याचिका खारिज कर दी और एकल न्यायाधीश पीठ के आदेश को बरकरार रखा। खंडपीठ ने यह भी कहा कि सर्वोच्च न्यायालय की हालिया टिप्पणी के अनुसार, एकल न्यायाधीश पीठ के आदेश को चुनौती देने वाली शाहजहां की याचिका स्वीकार्य नहीं है।

देश दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा- 'शिक्षा बेचने की चीज नहीं है'

दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने विधानसभा में पेश किया स्कूल शिक्षा शुल्क निर्धारण बिल 2025

एजेंसी । दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने दिल्ली विधानसभा में 'दिल्ली स्कूल शिक्षा (फीस निर्धारण एवं विनियमन में पारदर्शिता) विधेयक, 2025' पेश किया। उन्होंने कहा, ÷शिक्षा बेचने की चीज नहीं है, यह विधेयक शिक्षा के व्यावसायीकरण को रोकने के लिए लाया गया है। हम यह विधेयक उन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए ला रहे हैं जो शिक्षा बेच रहे हैं।÷

29 अप्रैल को पारित कैबिनेट द्वारा अनुमोदित अध्यादेश के अनुसार, यह विधेयक मनमाने ढंग से फीस बढ़ाने वाले स्कूलों पर कठोर दंड का प्रावधान करता है। पहली बार उल्लंघन करने पर, स्कूलों पर 1 लाख रुपये से 5 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा, और बार-बार उल्लंघन करने पर 2 लाख रुपये से 10 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। यदि स्कूल निर्धारित समय सीमा के भीतर राशि वापस नहीं करता है, तो जुर्माना 20 दिनों के बाद दोगुना, 40 दिनों के बाद तिगुना और हर 20 दिन की देरी के साथ बढ़ता रहेगा। बार-बार उल्लंघन करने पर स्कूल प्रबंधन में आधिकारिक पदों पर रहने पर प्रतिबंध लग सकता है और भविष्य में शुल्क संशोधन का प्रस्ताव देने का अधिकार भी छिन सकता है।

बता दें कि सीएम रेखा गुप्ता ने रविवार को साफ किया है कि ये बिल अभिभावकों के हित में है और स्कूलों की मनमानी पर लगाम लगाएगा। लेकिन आम आदमी पार्टी ने बिल का कड़ा विरोध शुरू कर दिया है। आप नेता आतिशी समेत सीनियर नेताओं का आरोप है कि सरकार इस बिल के जरिए निजी स्कूलों को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रही है। आप ने सवाल उठाया कि अगर बिल वाकई जनहित में है तो सरकार ने इसे अब तक सार्वजनिक क्यों नहीं किया। इस बिल के कानून के रूप में बदलने के बाद प्राइवेट स्कूल्स की फीस स्ट्रक्चर पर कड़े नियम लागू हो जाएंगे, जिससे मनमानी फीस बढ़ोतरी पर लगाम लग सकेगी।

बांग्लादेश सरकार पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के घर को म्यूजियम बनाएगी

नई दिल्ली

15 साल इस घर में रहीं पूर्व PM, पिछले साल यहां तोड़फोड़

बांग्लादेश सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के पुराने आधिकारिक घर 'गणभवन' को म्यूजियम में बदलने का फैसला किया है। इसे 'जुलाई क्रांति स्मारक संग्रहालय' कहा जाएगा।

शेख हसीना के पिता और बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति शेख मुजीबुर्रहमान ने इस घर को फिर से बनवाया था। इससे पहले इस जगह को एस्टेट राजबाड़ी के नाम से जाना जाता था।

गणभवन ढाका के शेर-ए-बांग्ला नगर में है, जो संसद भवन के पास है। बांग्लादेश सरकार इसे देश के नेता के आधिकारिक घर के रूप में इस्तेमाल करती थी। शेख हसीना 2010 में यहां रहने आई थीं और 5 अगस्त 2024 तक यानी 15 साल यही उनका घर रहा। पिछले साल उनके तख्तापलट के कुछ देर बाद ही यहां तोड़फोड़ और लूटमार शुरू हो गई थी। प्रदर्शनकारी शेख हसीना के घर पर चढ़ गए थे।

गणभवन से महिलाओं के चुराए गए कपड़ों को हवा में लहराता एक प्रदर्शनकारी। गणभवन से महिलाओं के चुराए गए कपड़ों को हवा में लहराता एक प्रदर्शनकारी। शेख मुजीब से जुड़ी कई निशानियों पर हमला बांग्लादेश में बीते एक साल से लगातार शेख हसीना और उनके पिता से जुड़ी कई निशानियों पर हमला किया जा रहा है। बीते 12 महीने में शेख मुजीब की मूर्ति को तोड़ा गया और कई सार्वजनिक स्थानों पर लगी नेमप्लेट को भी हटा दिया गया। इसके अलावा स्कूल की किताबों में उनसे जुड़े कई चैप्टर को बदला गया और नोट पर लगी तस्वीरों को भी हटा दिया गया। अंतरिम सरकार ने आजादी और संस्थापक से जुड़े दिनों की 8 सरकारी छुट्टियां भी कैंसिल कर दी थी। शेख मुजीबुर्रहमान बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति थे। वह 17 अप्रैल 1971 से लेकर 15 अगस्त 1975 तक देश के प्रधानमंत्री भी रहे थे। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के पिता मुजीबुर्रहमान ने बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजादी दिलाने में भी बड़ी भूमिका निभाई थी। 15 अगस्त 1975 को शेख मुजीबुर्रहमान की उनके घर पर ही हत्या कर दी गई थी।

बीते साल भीड़ ने हमला कर महिलाओं के कपड़े भी लूट लिए थे भीड़ ने यहां से साड़ियां, सजावटी सामान, घड़ियां, सोफे, लग्जरी हैंडबैग, टेलीविजन, मछलियां और यहां तक कि महिलाओं के कपड़े तक लूट लिए थे। सोशल मीडिया पर लूट की तस्वीरें वायरल हो गई थीं। बाद में अधिकारियों ने दावा किया कि लूटा गया सामान वापस कर दिया गया। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस की लीडरशिप वाली अंतरिम सरकार ने गणभवन को शेख हसीना के कुशासन की निशानी बताते हुए इसे म्यूजियम बनाने की घोषणा की। यह म्यूजियम पिछले साल की हिंसा में मारे गए प्रदर्शनकारियों की याद में बनाया जा रहा है। बांग्लादेश के संस्कृति मंत्रालय ने इस म्यूजियम के मैनेजमेंट के लिए 200 पदों का प्रस्ताव दिया है। गणभवन के तालाब में पाली हुई मछलियों के पकड़ते हुए प्रदर्शनकारी। कई प्रदर्शनकारियों यहां पाले गए जानवर चोरी करके अपने घर ले गए थे। कई प्रदर्शनकारियों यहां पाले गए जानवर चोरी करके अपने घर ले गए थे।

छत्तीसगढ़ में विरासत संरक्षण के लिए केंद्र का बड़ा कदम, 26.24 करोड़ का आवंटन

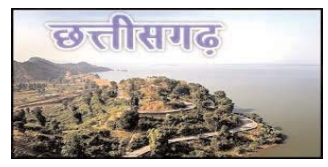

रायपुर,। भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ में स्मारकों, किलों और अन्य धरोहर संरचनाओं की पहचान और संरक्षण के लिए व्यापक सर्वेक्षण किया है और पिछले पाँच वर्षों में इन कार्यों के लिए 26.24 करोड़ का आवंटन किया है। यह जानकारी संस्कृति और पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सांसद श्रीमती फूलो देवी नेताम के प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

मंत्री ने बताया कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने वर्ष 2014-15 से 2024-25 तक छत्तीसगढ़ में गांव-गांव सर्वेक्षण किया। इस दौरान 764 गांवों का सर्वेक्षण हुआ, जिनमें से 73 गांवों में प्राचीन अवशेष पाए गए, जो राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को दर्शाते हैं।

उन्होंने आगे कहा कि केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ में केंद्र संरक्षित स्मारकों और स्थलों की मरम्मत, संरक्षण और रखरखाव के लिए वर्ष 2020-21 में 2.89 करोड़, 2021-22 में ?4.78 करोड़, 2022-23 में ?7.50 करोड़, 2023-24 में ?5.94 करोड़ और 2024-25 में ?5.13 करोड़ का आवंटन किया। हर वर्ष यह राशि पूरी तरह खर्च की गई। मंत्रालय ने कहा कि यह पहल देश की मूर्त सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित रखने और आने वाली पीढ़ियों के लिए ऐतिहासिक महत्व के स्मारकों व स्थलों को सुरक्षित बनाने के लिए लगातार चलाए जा रहे प्रयासों का हिस्सा है।

लोकशक्ति
www.lokshakti.in

पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 20 वीं किस्त के रूप में 15.91 करोड़ रुपये हस्तांतरित हुए

जिले के 73,555 किसानों के बैंक खातों में

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना के तहत देशभर के किसानों के बैंक खातों में 20,500 करोड़ का किया हस्तांतरण

कृषि विज्ञान केंद्र डुमरबहार में पीएम किसान सम्मेलन का हुआ सीधा प्रसारण

जशपुरनगर । प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज पीएम किसान सम्मान निधि योजना के 20 वीं किस्त के तहत देशभर के किसानों के बैंक खातों में 20,500 करोड़ रुपये से अधिक की राशि का डिजिटल माध्यम से स्थानांतरण किया। इस अवसर पर जशपुर जिले के 73,555 किसानों के खाते में कुल 15.91 करोड़ रुपये हस्तांतरित हुआ। जिले में इस अवसर पर कृषि विज्ञान केंद्र डुमरबहार में पीएम किसान सम्मेलन का सीधा प्रसारण किया गया। कार्यक्रम का आयोजन कृषि विज्ञान केंद्र एवं कृषि विभाग, जशपुर के संयुक्त तत्वावधान में किया गया था।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री सालिक साय ने कहा कि भारत सरकार किसानों को समर्थ और सशक्त बनाने के लिए सतत प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकारें किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए आवश्यक संसाधन एवं तकनीकी सहायता उपलब्ध करा रही हैं। उन्होंने कृषकों को मशरूम उत्पादन जैसी अतिरिक्त आय सृजन गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरित करते हुए कृषि विज्ञान केंद्र में आयोजित मशरूम प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। कार्यक्रम में

जशपुर के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख श्री राकेश कुमार भगत द्वारा इस प्रक्षेत्र में चल रहे विभिन्न कृषि संबंधी गतिविधियों पर विस्तारपूर्वक जानकारी दिया गया।

उप संचालक कृषि श्री एम.आर. भगत ने किसानों से अपील की कि वे शत-प्रतिशत किसान क्रेडिट कार्ड बनवाएं तथा लखपति दीदी योजना और पीएम किसान योजना में अभी तक वंचित किसानों का शीघ्र पंजीयन कराएं। उन्होंने कहा कि यदि किसी किसान की किस्त तकनीकी त्रुटियों के कारण परेशानी हो रही है तो वे अपने क्षेत्र के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी अथवा कृषि विभाग से संपर्क कर समस्या का समाधान कर सकते हैं। कार्यक्रम में केंद्र व राज्य सरकार के विभिन्न विभागीय योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को शासकीय योजनाओं के बारे में किसानों को जागरूक करने और इससे लाभान्वित करने को कहा गया।

इस अवसर पर कृषक उपज मंडी समिति पत्थलगांव के सचिव श्री राकेश खैरवार ने मंडी प्रांगण में बने फल-सब्जी दुकानों के सम्बंध में किसानों को विस्तृत जानकारी प्रदान की। कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केन्द्र कुनकुरी के अधिष्ठाता डॉ. ए.के. सिंन्हा ने उन्नत कृषि तकनीकी, जैविक खेती, और समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन एवं कीट व्याधि नियंत्रण के सम्बंध में किसानों को विस्तार से मार्गदर्शन दिया।

पीएम किसान सम्मान निधि योजना का उद्देश्य

छोटे एवं सीमांत किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक, सिंचाई आदि के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना। प्रतिवर्ष 6,000 की सहायता प्रदान कर खेती के खर्च में सहायता करना। किसानों पर ऋण भार को कम करना।

धर्मांतरण छत्तीसगढ़ के लिए कलंक – विष्णुदेव साय

रायपुर। प्रदेश में धर्मांतरण को लेकर मचे सियासी तूफान के बीच मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण एक सामाजिक कलंक बन चुका है, जिसे समाप्त करने के लिए सरकार निर्णायक लड़ाई लड़ रही है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि इस समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए सख्त और ठोस कदम उठाए जाएंगे।

गौरतलब है कि कुछ दिनों पहले दुर्ग जिले से केरल की दो ननों को धर्मांतरण और मानव तस्करी के आरोपों के चलते गिरफ्तार किया गया था। इस घटना ने राजनीतिक हलकों में काफी हलचल मचा दी थी। मामला दिल्ली तक पहुंचा और राज्य की राजनीति में भी उबाल देखने को मिला।

हालांकि, शनिवार को एनआईए कोर्ट ने दोनों ननों को जमानत दे दी, जिसके बाद उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया है। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर राज्य में धर्मांतरण को लेकर जारी बहस को तेज कर दिया है।

यूजी इंजीनियरिंग प्रोग्राम को मिला राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड एनबीए से वर्ष 2028 तक मान्यता विस्तार

रायपुर । शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, बिलासपुर (कोनी), छत्तीसगढ़ को उच्च तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई है। महाविद्यालय के यांत्रिकी अभियांत्रिकी (मैकनिकल इंजीनियरिंग) स्नातक प्रोग्राम को राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन) द्वारा शैक्षणिक सत्र 2025-26 से 2027-28 तक की मान्यता प्रदान की गई है।

किसी मरीज या अस्पताल को नहीं हुआ गुणवत्ताहीन कैल्शियम टैबलेट्स का वितरण

प्रारंभिक जांच में ही पकड़ी गई खराबी, तुरंत बैच पर लगाई रोक

रायपुर । गुणवत्ताहीन कैल्शियम की गोलियों का वितरण किसी भी मरीज या अस्पताल को नहीं किया गया है। कैल्शियम विटामिन डी 3 टैबलेट्स की खराबी वेयरहाऊस के कर्मियों ने प्रारंभिक जांच में ही पकड़ ली थी। कर्मियों ने इन टैबलेट्स के स्ट्रिप्स से बाहर निकालने पर ही टूटने की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों, सीजीएमएससी के क्वालिटी कंट्रोल विभाग और मुख्यालय को दी थी। इसी सूचना पर इन टैबलेट्स के बैच को तत्काल ब्लॉक कर दिया गया था और सप्लाईकर्ता संस्था के प्रतिनिधि को स्पष्टीकरण के लिए बुलाया गया था। स्ट्रिप्स से निकालते ही टूटने वाली कैल्शियम विटामिन डी 3 टैबलेट्स को किसी भी मरीज को नहीं दिया गया है नही इन टैबलेट्स को किसी अस्पताल में भेजा गया है। सीजीएमएससी से मिली जानकारी के अनुसार कैल्शियम विटामिन डी 3 की 500 मिली ग्राम की टैबलेट हेल्थ लाईफफार्म लिमिटेड द्वारा सप्लाई की गई थी। कुल 65 बॉक्स्सों में 65 सौ यूनिट की यह खेप कोरबा वेयरहाऊस को प्राप्त हुई थी। टेबलेट्स के प्राप्त होते ही वेयरहाऊस में ही कर्मियों द्वारा इसका प्रारंभिक परीक्षण किया गया था। परीक्षण में पाया गया था कि टेबलेटस स्ट्रिप्स से बाहर निकालते ही टूट रही हैं। कर्मियों ने इसकी सूचना तत्काल सीजीएमएससी के क्वालिटी कंट्रोल विभाग को दी और इन गुणवत्ताहीन टैबलेट्स के पूरे बैच को ब्लॉक किया गया। सीजीएमएससी ने बताया कि इस खेप का अभी तक कोई मटेरियल प्राप्ति प्रमाण पत्र तैयार नहीं किया गया है। सीजीएमएससी की नीति के अनुसार कोई भी दवा बिना मटेरियल प्राप्ति सर्टिफिकेट के न तो इनवेंटरी में शामिल की जाती है नही किसी संस्था को वितरित की जाती है। ऐसे में गुणवत्ताहीन कैल्शियम विटामिन डी 3 टेबलेट्स को न किसी मरीज को दिया गया है न ही किसी सरकारी अस्पताल में पहुंचाया गया है। प्रदायकर्ता संस्था हेल्दी लाईफ फार्म प्राईवेट लिमिटेड को उपस्थित होकर सैंपल प्रस्तुत करने और स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही प्रदायकर्ता संस्था को खराब बैच वाली दवाओं को बदलकर नई दवाएं देने के भी निर्देश दिए गए हैं। सप्लायर द्वारा टेंडर शर्तों के अनुसार उचित कार्यवाही नहीं करने पर दंडात्मक कार्रवाई करने की चेतावनी भी सीजीएमएससी ने दी हैं। सीजीएमएससी ने छत्तीसगढ़ वासियों को आश्वस्त किया है कि राज्य में दवा आपूर्ति प्रणाली न केवल सतर्क है बल्कि गुणवत्ता निगरानी व्यवस्था भी पूरी तरह से मजबूत है। दवा की सप्लाई होती ही सबसे पहले वेयर हाऊस में ही हर एक बैच का निरीक्षण-परीक्षण होता है। सभी दवाओं का परीक्षण एन.ए.बी.एल. मान्यता प्राप्त लैबों में कराया जाता है। सीजीएमएससी ने यह भी बताया कि जनता को केवल गुणवत्तायुक्त प्रमाणित दवाई ही उपलब्ध कराई जाती हैं। गुणवत्ताहीन पाए जाने पर दोषपूर्ण बैच को तुरंत रोककर इसका वितरण प्रतिबंधित किया जाता है। दोषी सप्लायर के विरूद्ध तेजी से कार्रवाई की जाती है।

पानी की जांचकर खोली आंखे, पीने के पानी की गुणवत्ता पर सजग हुए ग्रामीण

बीजापुर/रायपुर । धुर नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले में अब विकास के साथ सामाजिक-स्वास्थ्य और अन्य क्षेत्रों में भी जागरूकता बढ़ रही है। प्रशासन इसके लिए तरह-तरह से प्रयास कर लोगों को समझाईश दे रहा है। बीजापुर जिले के भोपालपटनम एवं उसूर विकासखंडों के अंतर्गत आने वाले ग्राम बामनपुर, गुंजेपरती और नंबी में जल जीवन मिशन के तहत जल सुरक्षा और स्वच्छता को लेकर ऐसे ही एक अनोखी और प्रेरणादायक जनजागरूकता पहल की गई।

इन गांवों में हर घर नल से जल योजना के अंतर्गत पेयजल सुविधा तो उपलब्ध थी, फिर भी कुछ ग्रामीण परंपरागत आदतों या जानकारी के अभाव में नदी और नालों के पानी का उपयोग पीने के लिए कर रहे थे। इससे स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्याओं की संभावना बनी हुई थी। जल-जीवन मिशन की समीक्षा बैठक में प्रशासन ने तय किया कि ग्रामीणों को जल की गुणवता और उससे जुड़ी स्वास्थ्य संबंधी जोखिमों के बारे में व्यावहारिक तरीके से समझाने का अभियान चलाया जाएगा। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अधिकारियों की देखरेख में यह अभियान प्रारंभ किया गया।

जिला जल परीक्षण प्रयोगशाला की केमिस्ट के नेतृत्व में दल बनाकर गांवों में भेजा गया। वहाँ पहुँचकर उन्होंने सरपंच, सचिव, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मितानिन और ग्रामवासियों की उपस्थिति में नदी नाले के जल और नल से प्राप्त जल का परीक्षण करके अंतर को सबके सामने प्रस्तुत किया। जब ग्रामीणों ने स्वयं देखा कि नदी नाला के जल में हानिकारक तत्व उपस्थित हैं जबकि घर में लगे नल का जल साफ और सुरक्षित है।

आरपीएफ की पहली महिला डीजी बनीं सोनाली मिश्रा, छत्तीसगढ़ से रहा है गहरा नाता

रायपुर । देश की रेलवे सुरक्षा व्यवस्था में एक नया इतिहास रचते हुए, आईपीएस अधिकारी सोनाली मिश्रा को रेलवे सुरक्षा बल (RPF) की पहली महिला महानिदेशक (DG) नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार की कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने उनकी नियुक्ति को 31 अक्टूबर 2026 तक के लिए मंजूरी दे दी है। वे मध्यप्रदेश कैडर की 1993 बैच की वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं और अपनी दक्षता, अनुशासन और नेतृत्व कौशल के लिए जानी जाती हैं।

सोनाली मिश्रा का छत्तीसगढ़ से भी एक खास रिश्ता रहा है। जब छत्तीसगढ़ का गठन नहीं हुआ था और वह मध्यप्रदेश का हिस्सा था, तब अपने करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिलासपुर में सीएसपी और एएसपी के रूप में अहम जिम्मेदारियां संभाली थीं। राज्य पुनर्गठन के बाद वे मध्यप्रदेश कैडर में लौट गईं, लेकिन छत्तीसगढ़ की उनकी सेवा को अब भी याद किया जाता है। लगभग तीन दशकों के सेवा अनुभव के दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है। आरपीएफ में नियुक्ति से पहले वे एडीजी (चयन एवं भर्ती) के पद पर कार्यरत थीं। इसके अलावा उन्होंने पुलिस प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, भोपाल और मध्यप्रदेश पुलिस अकादमी में भी नेतृत्व भूमिका निभाई है। उनका अनुभव सिर्फ राष्ट्रीय ही नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी रहा है। उन्होंने सीबीआई, बीएसएफ और संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन (कोसोवो) में भी सेवा दी है। उनकी सेवाओं के लिए उन्हें राष्ट्रपति पुलिस पदक (विशिष्ट सेवा) और पुलिस पदक (सराहनीय सेवा) जैसे कई प्रतिष्ठित सम्मान भी मिल चुके हैं।

सोनाली मिश्रा की यह नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब रेलवे सुरक्षा बल को नई चुनौतियों और तकनीकी बदलावों से जूझना पड़ रहा है। उम्मीद की जा रही है कि उनके नेतृत्व में RPF का आधुनिकीकरण, क्षमता निर्माण और यात्रियों की सुरक्षा को लेकर नई दिशा मिलेगी।

सांसद कश्यप ने रेल सुविधा विस्तार और जनजातीय गौरव को लेकर केंद्रीय रेल मंत्री को सौंपा पत्र

जगदलपुर । बस्तर लोकसभा क्षेत्र के सांसद महेश कश्यप ने केंद्रीय रेल, सूचना प्रसारण एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र सौंपा। इस पत्र के माध्यम से उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बस्तर को मिली चार नई रेल परियोजनाओं की स्वीकृति पर आभार प्रकट करते हुए क्षेत्र के और अधिक समग्र विकास के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव एवं मांगें भी प्रस्तुत की हैं। सांसद कश्यप ने लिखा कि आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि बस्तर जैसे दूरस्थ और आदिवासी बहुल क्षेत्र को राष्ट्रीय विकास योजनाओं में केंद्र सरकार ने इतनी प्राथमिकता दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की संवेदनशीलता के परिणाम स्वरूप बस्तर को एक साथ चार रेल परियोजनाओं की सौगात मिली है, जो निश्चित ही आने वाले वर्षों में इस क्षेत्र की दिशा और दशा को बदलने वाली साबित होंगी। विशेषकर प्रस्तावित रेल लाइनें न केवल यात्री सुविधा बढ़ाएंगी, बल्कि इन

इलाकों में व्यापार, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता में भी गुणात्मक परिवर्तन लाएंगी। महेश कश्यप ने यह भी कहा है कि रावघाट से जगदलपुर तक स्वीकृत रेल लाइन का कार्य शीघ्र प्रारंभ हो और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर-कमलों से हो, इसके लिए उन्होंने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से विशेष आग्रह किया। यह रेल मार्ग बस्तर को छत्तीसगढ़ के सभी दिशाओं के हिस्सों से जोड़ने में सहायक होगा और राज्य के आंतरिक संपर्क को नया विस्तार देगा। इसके अतिरिक्त सांसद श्री कश्यप ने ओडिशा के कोरापुट से प्रस्तावित रेल मार्ग को छत्तीसगढ़ के सुदूरवर्ती नक्सल प्रभावित क्षेत्र सुकमा से जोड़ने की मांग की है। उन्होंने लिखा कि यह जोड़ न केवल भौगोलिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इससे सुकमा जैसे जिले को भी रेल सुविधा से जोड़ा जा सकेगा, जो अब तक ऐसे किसी भी आधारभूत ढांचे से वंचित रहा है। इससे न केवल क्षेत्रीय समावेश बढ़ेगा, बल्कि नक्सल प्रभावित इलाकों में विकास की पहुंच को भी सुदृढ़ आधार मिलेगा।

जनजातीय कॉरिडोर की मांग

सांसद महेश कश्यप ने बस्तर की सांस्कृतिक विरासत और जनजातीय अस्मिता को संरक्षित एवं प्रोत्साहित करने की दिशा में एक दूरदर्शी प्रस्ताव भी दिया। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की कि छत्तीसगढ़, ओडिशा, तेलंगाना, महाराष्ट्र और आंध्रप्रदेश की सीमाओं से लगे जनजातीय बहुल अंचलों को समाहित करते हुए एक विशेष जनजातीय गौरव बस्तर कॉरिडोर की घोषणा की जाए। सांसद कश्यप ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो जनजातीय पुनर्जागरण की लहर चल रही है, उसी को मूर्त रूप देने के लिए बस्तर जैसा क्षेत्र भी रोल मॉडल बन सकता है।

समूह से जुड़कर बनाई पहचान और बनीं महिला सशक्तिकरण की प्रेरणा

रायपुर,

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के गृह जिला जशपुर की ग्रामीण महिलाएं आत्मनिर्भरता की दिशा में नए आयाम स्थापित कर रही हैं। जिले के कांसाबेल विकासखंड अंतर्गत ग्राम केनाडाड़ की श्रीमती शशिकला खलखो ने बिहान योजना के माध्यम से स्वावलंबन की मिसाल पेश की है। एक सामान्य गृहिणी से सफल उद्यमी बनने का उनका यह सफर अन्य महिलाओं के लिए भी प्रेरणास्रोत है।

श्रीमती शशिकला खलखो वर्ष 2008 से ÷जीवन ज्योति स्व-सहायता समूह÷ की सक्रिय सदस्य हैं। 11 सदस्यीय इस समूह के माध्यम से उन्होंने सामूहिक खेती-किसानी के कार्यों में सहभागिता करते हुए अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ किया। बिहान योजना से जुड़ने के पश्चात उनके जीवन में बदलाव आया, उन्होंने बच्चों की शिक्षा के साथ-साथ अपने आप को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाया। अपनी उद्यमशीलता को विस्तार देते हुए हाल ही में उन्होंने होटल व्यवसाय प्रारंभ किया है। इस हेतु उन्हें मुद्रा योजना के अंतर्गत ऋण तथा सामुदायिक निवेश निधि (सीआईएफ) मद से 60 हजार रुपये की सहायता प्राप्त हुई। उन्होंने बताया कि होटल संचालन की यह नई शुरुआत उनके लिए उत्साहजनक रही है और प्रारंभिक माह में ही उन्हें अच्छी आय प्राप्त हुई है।

श्रीमती खलखो पूर्व में खाद्य विभाग के अंतर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) की दुकान का संचालन भी कर चुकी हैं। इसके अतिरिक्त उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का आवास, महतारी वंदना योजना के अंतर्गत मासिक 1000 रूपए की आर्थिक सहायता तथा उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस कनेक्शन की सुविधा प्राप्त हुई है। श्रीमती शशिकला खलखो ने अपनी सफलता का श्रेय राज्य सरकार की महिला सशक्तिकरण योजनाओं को देते हुए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति विशेष आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि शासन की योजनाओं ने उन्हें आत्मनिर्भर बनने का अवसर दिया है और अब वे अन्य महिलाओं को भी प्रेरित कर रही हैं।

आठ साल बाद हुई कौशल प्रतियोगिताएं, ढाई हजार से अधिक युवाओं ने दिखाई अपनी प्रतिभा

राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए 288 का चयन

मुख्यमंत्री ने दी बधाई, कहा - युवाओं के भविष्य को सशक्त बनाने और आत्म निर्भर छत्तीसगढ़ की ओर मजबूत कदम

रायपुर । छत्तीसगढ़ में करीब 8 साल बाद युवाओं को अपना कौशल दिखाने का मौका मिला है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली सरकार ने इस साल कौशल तिहार 2025 के तहत् युवाओं को यह मौका दिया है। राज्य कौशल विकास प्राधिकरण (सीएसएसडीए) द्वारा 21 जुलाई से 31 जुलाई 2025 तक राज्य के सभी जिलों में 10 दिन तक ''कौशल तिहार 2025'' का आयोजन बड़े ही उत्साह और धूमधाम से किया गया। राज्य के सभी जिलों में चयनित प्रतिभागियों ने अपने-अपने क्षेत्र में शानदार प्रदर्शन किया। इस प्रतियोगिता में कुल 2 हजार 530 युवाओं ने भाग लिया, जिसमें से 288 प्रतिभागियों का चयन राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए हुआ। इस आयोजन से प्रदेश के युवाओं को न केवल अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिला, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर और रोजगारमुखी बनने की प्रेरणा भी मिली। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य युवाओं को कौशल विकास के प्रति जागरूक करना और उन्हें भारत स्किल्स 2026 व वर्ल्ड स्किल्स 2026 जैसी राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करना था। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए चयनित सभी प्रतिभागियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने अपने बधाई संदेश में कहा कि यह आयोजन केवल एक प्रतियोगिता नहीं है, बल्कि छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए आशा, आत्मविश्वास व अवसर का भी प्रतीक है। यह राज्य सरकार की युवाओं के भविष्य को सशक्त बनाने की एक मजबूत और सराहनीय पहल है। यह आयोजन न केवल रोजगार की दिशा में सहायक है, बल्कि आत्मनिर्भर छत्तीसगढ़ की ओर एक सकारात्मक कदम भी है।

छत्तीसगढ़ राज्य में इस प्रकार की कौशल प्रतियोगिता का आयोजन आठ साल पहले वर्ष 2017 में किया गया था। इसके बाद अब दूसरी बार यह आयोजन मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व और कौशल विकास मंत्री श्री केदार कश्यप के मार्गदर्शन में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।

कलेक्टर ने अधिकारियों और ठेकेदारों को दी चेतावनी विकास कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी

सड़क के निर्माण कार्यों में गुणवत्ता के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा

जिसकी लापरवाही उन्हीं के ऊपर होगी कार्रवाई

आम जनता को अच्छी सुविधाएं देना प्रशासन की पहली प्राथमिकता

जशपुर । कलेक्टर श्री रोहित व्यास ने शनिवार को कलेक्टोरेट सभाकक्ष में सभी निर्माण एजेंसी लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का विभाग, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के विभाग, गृह निर्माण मंडल, राष्ट्रीय राजमार्ग, आर ई एस विभाग ,नगरीय निकाय सहित अधिकारियों और ठेकेदारों की संयुक्त बैठक लेकर विभागीय निर्माण कार्यों की विस्तार से समीक्षा की। कलेक्टर ने सभी अधिकारियों और ठेकेदारों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और गुणवत्ता के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा।

कलेक्टर ने बताया कि जशपुर में विकास कार्यों के पूल पुलिया, सड़क, स्कूल, आंगनबाड़ी, स्वास्थ्य केन्द्र, स्टेडियम और अधोसंरचना के विभिन्न विकास कार्यों की स्वीकृति दी गई। उन कार्यों को गंभीरता से और समय सीमा में करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने बताया कि लगभग 1856 करोड़ रुपए के कार्यों की स्वीकृति मिल गई है। और आगे भी विकास कार्यों के लिए स्वीकृत मिलती रहेगी। कलेक्टर ने निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति पर गहरी नाराजगी व्यक्त की कलेक्टर ने कहा कि आम जनता को अच्छी सुविधाएं देना प्रशासन की पहली प्राथमिकता है। और इसमें किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। कलेक्टर ने निर्माण एजेंसी के अधिकारियों और ठेकेदारों को सख्त निर्देश दिए हैं। अपने कार्य शैली में सुधार लाएं लोगों के जनहित के लिए कार्य करें गुणवत्ता के साथ कार्यों को पूर्ण करें। कलेक्टर ने कहा कि लापरवाही बरतने वाले कोई भी अधिकारी और ठेकेदार बच नहीं पाएंगे जिनकी गलती होगी उन पर कार्रवाई निश्चित है। इस अवसर पर डिप्टी कलेक्टर हरिओम द्विवेदी संबंधित विभाग के अधिकारीगण और कार्यपालन अभियंता और निर्माण एजेंसी के प्रतिनिधि उपस्थित थे। कलेक्टर ने समीक्षा बैठक में ठेकेदारों की समस्याओं का भी समाधान किया और आवश्यक दिशा-निर्देश। कलेक्टर ने पीएम जनमन योजना की भी समीक्षा की और सड़क निर्माण कार्यों को गंभीरता से करने के निर्देश दिए।

संपूर्णता अभियान में उत्कृष्ट कार्य करने वाले आकांक्षी जिलों और विकासखंडों को मुख्यमंत्री ने किया पुरस्कृत

सभी छह संकेतकों में पूर्ण संतृप्ति हासिल करने वाले दो जिलों और छह विकासखंडों को मिला स्वर्ण पदक

रायपुर । मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने संपूर्णता अभियान में निर्धारित लक्ष्यों को हासिल करने में उत्कृष्ट कार्य करने वाले आकांक्षी जिलों और विकासखंडों को पुरस्कृत किया। उन्होंने आज राजधानी रायपुर के नवीन विश्राम भवन में आयोजित कार्यक्रम में जुलाई-2024 से सितम्बर-2024 तक राज्य के आकांक्षी जिलों और आकांक्षी विकासखंडों में तीन महीनों तक संचालित संपूर्णता अभियान में निर्धारित संकेतकों को संतृप्त करने और लक्ष्यों को हासिल करने वाले जिलों और विकासखंडों को पुरस्कार प्रदान किए। उन्होंने इन जिलों और विकासखंडों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले विभिन्न विभागों के अधिकारियों-कर्मचारियों को भी पुरस्कृत किया। संपूर्णता अभियान के दौरान सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले आकांक्षी जिलों बस्तर और कोंडागांव तथा आकांक्षी विकासखंडों शंकरगढ़, मैनपुर, माकड़ी, कोयलीबेड़ा, ओरछा और प्रतापपुर को स्वर्ण पदक प्रदान किया गया। उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव और श्री विजय शर्मा, सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल तथा विधायक सर्वश्री सुनील सोनी, मोतीलाल साहू और गुरू खुशवंत साहेब भी सम्मान समारोह में शामिल हुए।मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत की संकल्पना में सभी वर्गों का विकास समाहित है। उन्होंने कहा कि दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वालों और विशेष पिछड़ी जनजातियों (क्क्कुञ्जलह्य) को विकास की सबसे ज्यादा जरूरत है। भारत सरकार ने इसे गहराई से समझकर प्रधानमंत्री जनमन योजना प्रारंभ की है। इस योजना से सुदूर वनांचलों में आवास, पेयजल, बिजली, सड़क और अन्य बुनियादी सुविधाएं पहुंच रही हैं। धरती आबा ग्राम उत्कर्ष अभियान जैसे कार्यक्रमों से जिसमें छत्तीसगढ़ के भी 6661 गांव शामिल हैं, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की दूरदर्शी सोच के अनुरूप विकास की रोशनी सुदूर गांवों तक पहुंच रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में केंद्र सरकार की आकांक्षी जिलों और विकासखंडों में शामिल गांव तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने अपने संबोधन में कहा कि देश में वर्ष 2018 से आकांक्षी जिलों में काम शुरू हुआ है। विकास की दौड़ में पिछड़े जिलों और विकासखंडों को आगे लाने का काम इसमें हो रहा है। इसके अंतर्गत शामिल गांवों में अलग-अलग सेक्टर में काम कर मानव सूचकांकों को सुधारा जा रहा है। उन्हें संतृप्ति के स्तर पर लाया जा रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि एक-एक व्यक्ति के विकास और कल्याण से विकसित छत्तीसगढ़ और विकसित भारत का मार्ग प्रशस्त होगा।

उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने समारोह में कहा कि आकांक्षी जिलों और विकासखंडों में भौतिक प्रगति से अलग मानव सूचकांकों को बेहतर करने के लिए काम किए जा रहे हैं।

दिव्यांग बच्चों के संरक्षण पर राज्यस्तरीय कार्यशाला का आयोजन

रायपुर। पुलिस महानिदेशक अरूणदेव गौतम के पहल पर सेफगार्डिंग इन्टरेस्ट ऑफचिल्ड्रन विथ डिसेबिलिटिस विषय पर छत्तीसगढ़ पुलिस एवं यूनिसेफ के संयुक्त तत्वाधान में एकदिवसीय कार्यषाला का आयोजन पुलिस मुख्यालय, नवा रायपुर में किया गया। कार्यक्रम के उद्घाटन अवसर पर पुलिस महानिरीक्षक अजय यादव ने कार्यषाला के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए कहा कि बाल संरक्षण की दिषा में लगातार कार्यशालाएं आयोजित की जा रही है। इसी कड़ी में जिलों में पदस्थ विशेष किशोर पुलिस इकाई (एसजेपीयू) एवं बाल कल्याण पुलिस अधिकारी(सीडब्ल्यूपीओ) सहित अन्य पुलिस अधिकारियों के लिए दिव्यांग बच्चों के अधिकारों के संरक्षण हेतु विषेष कार्यषाला का आयोजन किया गया है। इस कार्यषाला में एक ओर जहां दिव्यांग बच्चों से संबंधित प्रकरणों की विवेचना कैसी की जानी है वहीं दूसरी ओर पुलिस की संवेदनषीलता ऐसे बच्चों के साथ कैसी होनी चाहिए, इस पर प्रषिक्षण दिया जायेगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एवं पुलिस महानिदेषक अरूण देव गौतम ने अपने अतिथिय उद्बोधन में कहा कि वर्तमान समय में समाज में अत्यधिक परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं, जिसमें संयुक्त परिवारों व सामाजिक संस्थाओं का विघटन प्रमुख है, जिसके कारण बच्चों को घर व समाज से वह सर्पोट नही मिल पाता, जिसकी उसे आवष्यकता होती है। ऐसी स्थिति बच्चों को संरक्षित रखने की अतिरिक्त जिम्मेदारी पुलिस पर आ जाती है एवं पुलिस को कानून के पार जाकर बच्चों को समझना आवष्यक है, ताकि उनका भविष्य सुरक्षित हो सके। इस हेतु सभी स्टेकहोल्डर्स का सपोर्ट एवं भागीदारी अत्यावष्यक है तथा पुलिस को यथोचित पहल भी करनी होगी, क्योंकि ऐसे प्रकरणों में पुलिस फर्स्ट रिस्पांडर होती है, जिसके कारण जवाबदेही ज्यादा होती है। प्रषिक्षण सत्र के दौरान आस्था आर्गनाईजेषन, नई दिल्ली से विषय विषेषज्ञ श्री प्रतीक अग्रवाल एवं समाज कल्याण विभाग के सहायक संचालक श्री कमल सिंह भदोरिया ने प्रतिभागियों को महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए दिव्यांगता के इतिहास, समाज की जवाबदेही, मौजूद कानूनी प्रावधानों, पुलिस के कर्तव्य सहित दिव्यांग जन हेतु राज्य एवं केन्द्र सरकार की प्रचलित एवं आगामी योजनाओं पर प्रकाष डाला गया। कार्यषाला में विभिन्न जिलों व पुलिस मुख्यालय के 25 राजपत्रित अधिकारियों सहित कुल 135 पुलिस अधिकारियों ने भाग लेकर इसका लाभ उठाया।

विधायक पुरंदर मिश्रा ने करवाई चार महिलाओं की घर वापसी, किया जगन्नाथ सेना का गठन

रायपुर । छत्तीसगढ़ में एक बार फिर धर्मांतरण का मुद्दा राजनीतिक बहस के केंद्र में आ गया है। भाजपा विधायक पुरंदर मिश्रा ने 'जगन्नाथ सेना' नामक एक नए संगठन की शुरुआत के साथ इस मुद्दे पर बड़ा कदम उठाया है। मिश्रा ने हाल ही में धर्मांतरण कर चुकीं चार महिलाओं की 'घर वापसी' करवाई और सार्वजनिक रूप से उनके पैर धोकर, शॉल व श्रीफल भेंट कर उन्हें हिंदू धर्म में दोबारा शामिल किया।

विधायक मिश्रा ने बताया कि जगन्नाथ सेना हर रविवार सुबह 9 से 11 बजे तक धर्मविरोधी गतिविधियों के खिलाफ अभियान चलाएगी और राज्यभर में जनजागरूकता फैलाने का कार्य करेगी। उन्होंने कहा कि उड़िया बस्तियों में धर्मांतरण की खबरें सामने आने के बाद इस संगठन का गठन किया गया है। 'घर वापसी' कार्यक्रम से पहले मिश्रा ने कुंदरापारा से मधुपिल्लै चौक तक पदयात्रा कर धर्मांतरण विरोधी जनजागरण अभियान भी चलाया। मिश्रा ने कहा कि धर्मांतरण की किसी भी सूचना को शासन-प्रशासन तक पहुंचाया जाएगा और मिशनरी गतिविधियों को रोकने में यह संगठन अहम भूमिका निभाएगा। जब कांग्रेस ने सवाल उठाया कि भाजपा के पास बजरंग दल जैसे संगठन पहले से हैं, तो फिर नए संगठन की जरूरत क्यों? इस पर मिश्रा ने चुटीले अंदाज में जवाब देते हुए कहा, जब हम खाना खाते हैं तो चटनी भी होती है, जगन्नाथ सेना वही चटनी बनने का काम करेगी। वहीं, जब पत्रकारों ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा सीबीआई जांच की शक्तियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने की बात पूछी, तो मिश्रा ने पलटवार करते हुए कहा, जो जैसा करेगा, वैसा भरेगा। जो अपराध करेगा, उसे दंड मिलेगा।

आयुष्मान भारत योजना के क्रियान्वयन में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है छत्तीसगढ़

उपचार प्रदान करने के मामलों में देश भर में चौथे स्थान पर है छत्तीसगढ़

अब तक 78 लाख से अधिक लाभार्थियों ने सार्वजनिक और निजी अस्पतालों में निःशुल्क इलाज का लिया लाभ

रायपुर ।

छत्तीसगढ़ ने आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के सफल क्रियान्वयन में उल्लेखनीय प्रगति करते हुए देश भर में उपचार प्रदान करने के मामलों में चौथा स्थान प्राप्त किया है। यह सफलता राज्य सरकार की समावेशी और सुलभ स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है, विशेषकर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए।

राज्य सरकार ने एबी-पीएमजेएवाई को छत्तीसगढ़ की अपनी दो विशेष योजनाओं – शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना और मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना – के साथ प्रभावी रूप से समन्वित किया है। इस एकीकृत व्यवस्था से अधिकतम लाभार्थियों को नगद रहित इलाज की सुविधा मिल रही है। अब तक 78 लाख से अधिक लाभार्थी सार्वजनिक और निजी अस्पतालों में निःशुल्क इलाज का लाभ उठा चुके हैं। सार्वजनिक अस्पतालों में उपचार की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है, जो सरकार के स्वास्थ्य ढांचे में जनता के बढ़ते विश्वास का संकेत है।वरिष्ठ नागरिकों की स्वास्थ्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए वय वंदन योजना को भी राज्य में मजबूत किया गया है। इसके तहत अब तक 4.5 लाख से अधिक वय वंदन कार्ड बनाए जा चुके हैं, जिससे राज्य के 48त्न राशन कार्डधारी वृद्धजन लाभान्वित हुए हैं। पंजीयन को प्रोत्साहित करने के लिए आशा कार्यकर्ता, ग्राम सभाएं, शहरी स्वास्थ्य मंच, वृद्धाश्रमों और आवासीय कॉलोनियों में लक्षित पहुंच सुनिश्चित की गई है। साथ ही, 104 कॉल सेंटर के माध्यम से निरंतर संपर्क और सेवा सुविधा दी जा रही है। विशेष प्रयास के तहत 6 जिलों को 'वय मित्र जिला' के रूप में चिह्नित कर राज्य सरकार वरिष्ठ नागरिकों की स्वास्थ्य सुरक्षा को और अधिक सुदृढ़ बना रही है।

तखतपुर के युवक ने मेकाहारा अस्पताल के तीसरी मंजिल से कूदकर दी जान

रायपुर, (आरएनएस)।

बिलासपुर के तखतपुर में रहने वाले 38 साल के संतोष ध्रुव ने रायपुर के मेकाहारा अस्पताल की तीसरी मंजिल से कूदकर जान दे दी। संतोष को रेबीज के इलाज के लिए 21 जुलाई को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वो तीसरी मंजिल के आइसोलेशन वॉर्ड में थे, जहां से कूदने के बाद उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना के बाद अस्पताल में हड़कंप मच गया है। मृतक के परिवार वालों का आरोप है कि अस्पताल प्रशासन इस मामले को दबाने की कोशिश कर रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मिलने से भी उन्हें परेशानी हो रही है।

छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण पर सियासी जंग तेज, विधायक पुरंदर मिश्रा के बयान पर कांग्रेस का पलटवार

रायपुर । छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर राजनीतिक तापमान बढ़ गया है। रायपुर उत्तर से भाजपा विधायक पुरंदर मिश्रा द्वारा दिए गए एक विवादास्पद बयान ने माहौल और गर्मा दिया है। शनिवार को एयरपोर्ट पर मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराएगा, उसे पीटकर भगाया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि अब राम सेना के साथ जगन्नाथ सेना भी सक्रिय होगी, और ऐसे लोगों को राज्य से खदेड़ा जाएगा।

इस बयान के बाद कांग्रेस ने भाजपा पर जमकर हमला बोला। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए सवाल किया कि क्या भाजपा के पास पहले से मौजूद बजरंग दल, आरएसएस, और हिंदू सेना जैसे संगठन अब पर्याप्त नहीं हैं, जो उन्हें भगवान जगन्नाथ के नाम पर नई 'सेना' बनाने की जरूरत पड़ गई?

दीपक बैज का बयान

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने भाजपा विधायक पुरंदर मिश्रा के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि भाजपा के पास पहले से कई संगठन हैं, फिर भी नई जगन्नाथ सेना बनाना सिर्फ लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश है। उन्होंने पूछा कि क्या इन संगठनों को कानून तोड़ने की छूट दी गई है? बैज ने सरकार से ऐसे भड़काऊ बयानों और अराजकता फैलाने वालों पर तुरंत कार्रवाई की मांग की।

गृह मंत्री पर दीपक बैज का सवाल

दीपक बैज ने पूछा कि क्या गृह मंत्री विजय शर्मा ने भाजपा के संगठनों को कानून हाथ में लेने की छूट दे दी है? उन्होंने कहा कि असामाजिक तत्वों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि कानून का डर बना रहे और लोग सुरक्षित महसूस करें।

बस्तर के चहुंमुखी विकास के लिए सांसद महेश कश्यप की महत्वपूर्ण पहल, रेल सुविधा विस्तार व जनजातीय गौरव को लेकर केंद्रीय मंत्री को सौंपा पत्र

जगदलपुर। बस्तर लोकसभा क्षेत्र के सांसद महेश कश्यप ने केंद्रीय रेल, सूचना प्रसारण एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र सौंपा। इस पत्र के माध्यम से उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बस्तर को मिली चार नई रेल परियोजनाओं की स्वीकृति पर आभार प्रकट करते हुए क्षेत्र के और अधिक समग्र विकास के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव एवं मांगें भी प्रस्तुत की हैं। सांसद कश्यप ने लिखा कि आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि बस्तर जैसे दूरस्थ और आदिवासी बहुल क्षेत्र को राष्ट्रीय विकास योजनाओं में केंद्र सरकार ने इतनी प्राथमिकता दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की संवेदनशीलता के परिणाम स्वरूप बस्तर को एक साथ चार रेल परियोजनाओं की सौगात मिली है, जो निश्चित ही आने वाले वर्षों में इस क्षेत्र की दिशा और दशा को बदलने वाली साबित होंगी। विशेषकर प्रस्तावित रेल लाइनें न केवल यात्री सुविधा बढ़ाएंगी, बल्कि इन इलाकों में व्यापार, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता में भी गुणात्मक परिवर्तन लाएंगी। महेश कश्यप ने यह भी कहा है कि रावघाट से जगदलपुर तक स्वीकृत रेल लाइन का कार्य शीघ्र प्रारंभ हो और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर-कमलों से हो, इसके लिए उन्होंने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से विशेष आग्रह किया। यह रेल मार्ग बस्तर को छत्तीसगढ़ के सभी दिशाओं के हिस्सों से जोड़ने में सहायक होगा और राज्य के आंतरिक संपर्क को नया विस्तार देगा। इसके अतिरिक्त सांसद श्री कश्यप ने ओडिशा के कोरापुट से प्रस्तावित रेल मार्ग को छत्तीसगढ़ के सुदूरवर्ती नक्सल प्रभावित क्षेत्र सुकमा से जोड़ने की मांग की है। उन्होंने लिखा कि यह जोड़ न केवल भौगोलिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इससे सुकमा जैसे जिले को भी रेल सुविधा से जोड़ा जा सकेगा, जो अब तक ऐसे किसी भी आधारभूत ढांचे से वंचित रहा है। इससे न केवल क्षेत्रीय समावेश बढ़ेगा, बल्कि नक्सल प्रभावित इलाकों में विकास की पहुंच को भी सुदृढ़ आधार मिलेगा।

जनजातीय कॉरिडोर की मांग

सांसद महेश कश्यप ने बस्तर की सांस्कृतिक विरासत और जनजातीय अस्मिता को संरक्षित एवं प्रोत्साहित करने की दिशा में एक दूरदर्शी प्रस्ताव भी दिया। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की कि छत्तीसगढ़, ओडिशा, तेलंगाना, महाराष्ट्र और आंध्रप्रदेश की सीमाओं से लगे जनजातीय बहुल अंचलों को समाहित करते हुए एक विशेष जनजातीय गौरव बस्तर कॉरिडोर की घोषणा की जाए। सांसद कश्यप ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो जनजातीय पुनर्जागरण की लहर चल रही है, उसी को मूर्त रूप देने के लिए बस्तर जैसा क्षेत्र भी रोल मॉडल बन सकता है। मेरा विश्वास है कि केंद्र सरकार इन सुझावों पर शीघ्र निर्णय लेकर बस्तर के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास को नई ऊंचाई देगी।

गैस सिलेंडर चोरी करने वाले तीन आरोपी गिरफ्तार

रायपुर। थाना उरला पुलिस ने एक बड़ी कार्यवाही करते हुए रात में घर का ताला तोड़कर गैस सिलेंडर चोरी करने वाले तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से तीन एचपी गैस सिलेंडर एवं एक छोटा सिलेंडर, जिसकी कुल कीमत लगभग 10,000 है, बरामद किए गए हैं।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, प्रार्थी ने दिनांक 30 जुलाई 2025 को अपने किराए के मकान में ताला लगाकर अपने गृह ग्राम सोरला, जिला बेमेतरा चला गया था। अगले ही दिन 31 जुलाई को सुबह 5 बजे उसके पड़ोसी सूरज यादव ने फोन पर सूचना दी कि उसके घर का ताला टूटा हुआ है और घर का सामान बिखरा पड़ा है। प्रार्थी तत्काल अपनी पत्नी तारणी बाई साहू के साथ उरला लौटा और देखा कि उसके घर से तीन एचपी गैस सिलेंडर और एक छोटा सिलेंडर चोरी हो चुका था।

थाना उरला में अपराध क्रमांक 195/2025, धारा 331(4), 305 बी एन एस के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। जांच के दौरान संदेह के आधार पर सागर प्रजापति, रवि प्रजापति एवं राजा टंडन को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जिनसे पूछताछ में आरोप सिद्ध हुआ। आरोपियों ने कबूल किया कि उन्होंने दिनांक 30 जुलाई की रात में ताले लगे मकान से उक्त गैस सिलेंडर चोरी किए और उन्हें पंकज ऑक्सीजन के पास छुपाकर रखा। पुलिस ने मौके से चोरी गए सभी सिलेंडर जब्त कर लिए। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है।

लोकशक्ति
www.lokshakti.in

संपादकीय

शिक्षा में सुधार कर रही मोदी सरकार

देश की मोदी सरकार ने अपनी नीतियों से बदलाव किया है उसका नतीजा यह हुआ है कि आज देश में शिक्षित वर्ग की मानसिकता में बदलाव हुआ है। यूनिसेफ के अनुसार, 2024 में दुनिया भर में कम से कम 24.2 करोड़ छात्रों की शिक्षा चरम मौसम के कारण बाधित हुई। पूर्व में भी विभिन्न अध्ययनों में पाया गया है कि छात्रों पर उस तापमान का गहरा असर होता है, जिसके वे अभ्यस्त नहीं होते। तापमान में आने वाले जबरदस्त परिवर्तन सिर्फ पढाई के समय को ही नहीं प्रभावित करते बल्कि शिक्षा की गुणवत्ता पर भी असरकारक होते हैं। जलभराव, सड़कों की दुर्दशा व परिवहन संबंधी दिक्कतों के चलते कितने छात्र स्कूल जाने से वंचित रह जाते हैं, इस पर कोई प्रमाणिक अध्ययन नहीं किया जाता। स्कूली शिक्षा व स्वशिक्षा की गुणवत्ता में भारी अंतर होता है। बावजूद इसके मौसमी मार से शिक्षा को बचाने के लिए ऐसे तरीके प्रयोग में लाने की आवश्यकता बढ़ती जा रही है, जिनकी मदद से स्वअध्ययन व इंटरनेट द्वारा पढ़ाई संभव हो सके।

सच उलझ गया झूठ के बवंडर में ।
फरेब से तर-बतर तेरे किये वायदे,

झूठ का झरोखा थे तेरे सारे वायदे।

वो धंधा ही करता है मुखौटों का
झूठ से खेल, उठाता सारे फ़ायदे

अपनों से खतरा पीठ पर खंजर का
यूं ही टूट जाते संग जीने के वायदे।

सियासत आ गई बीच अपनों के अब
रिश्ते दरकिनार सर्वोपरि खुद के फायदे।

सच उलझ गया झूठ के बवंडर में संजीव।
लापता हैं सब कानून और सारे फायदे।

- संजीव ठाकुर

QR CODE SCAN
कर प्रेमेन्द्र अग्रवाल द्वारा लिखित पुस्तकें पढ़िये ऑनलाईन

PM : 2024 - Vishwa Sarkar Ka Vikalp

Modimaya_ Vaidik_Netritva

Rashtriya Ekta

DLF-Vadra-Bhrasht Tantra

Silent Assassins Jan11,1966

Accursed & Jihadi Neighbour

पीएम-किसान: किसानों के सशक्तिकरण और ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं के रूपांतरण का भारत का वैश्विक खाका

डॉ. प्रमोद मेहरदा

समावेशी विकास और ग्रामीण समृद्धि के सफर में, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना, भारत सरकार की एक अग्रणी पहल के रूप में उभर कर सामने आई है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 24 फरवरी 2019 को शुरू की गई, इस पहल ने लाखों छोटे एवं सीमांत किसानों के जीवन पर गहरा प्रभाव डाला है और पूरी तरह से डिजिटल, कुशल एवं पारदर्शी प्रणाली के जरिए प्रत्यक्ष आय सहायता प्रदान करने के एक वैश्विक मॉडल के रूप में खुद को स्थापित किया है।

प्रत्यक्ष समर्थन के जरिए किसानों का सशक्तिकरण

मूल रूप से,पीएम-किसान योजना पात्र किसान परिवारों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये की सहायता प्रदान करती है। यह सहायताराशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) प्रणाली के जरिए 2,000 रुपये की तीन बराबरकिस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में जमा की जाती है। इस सुव्यवस्थित एवंतकनीक-संचालित कदम से बिचौलियों की भूमिका, लाभ मिलने में होने वाली देरी और त्रुटि की गुंजाइशखत्म होतीहै और एक-एक पाई इच्छित लाभार्थी तक पहुंचना सुनिश्चित होता है।

इस योजना की शुरुआत से लेकर अब-तक,कुल 3.69 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि किसानों को हस्तांतरित की जा चुकी है। इस प्रकार, पीएम-किसान दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल रूप से क्रियान्वित नकद हस्तांतरण कार्यक्रमों में से एक बन गया है। आंकड़ों से परे, यह कदम सब्सिडी से हटकर सशक्तिकरण की दिशा में बढ़ने संबंधीएक बदलाव का प्रतीक है।बातचाहे बीज की हो या उपकरण या शिक्षा या फिर स्वास्थ्य की, इस योजना से किसानों को यह तय करने की आजादी मिलती है कि वे इस सहायता का सबसे बेहतरइस्तेमाल कैसे करें।

भारत के छोटे किसानों के हित में एक परिवर्तनकारी कदम

दो हेक्टेयर से कम जमीन वाले भारत के 85प्रतिशत से अधिक किसानों के लिए ये लाभ बुवाई या कटाई के मौसम में एक अहम आर्थिक सेतु का काम करते हैं। ये लाभ अल्पकालिक नकदी प्रवाह के तनाव को कम करते हैं, अनौपचारिक ऋण पर निर्भरता में कमीलाते हैंऔर संकट के समय एक सुरक्षा कवच प्रदान करते हैं।

वित्तीय सहायता से कहीं बढ़कर, पीएम-किसान योजना समावेशिता, सम्मान और राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में एक भागीदार के रूप में किसान की मान्यता का प्रतीक है।

डिजिटल शासन की श्रेष्ठता

पीएम-किसान की सफलता का श्रेय भारत के मजबूत डिजिटल बुनियादी ढांचे को जाता है। जेएएम की तिकड़ी -जन धन बैंक खाते, आधार बायोमेट्रिक पहचान और मोबाइल कनेक्टिविटी - ने बड़े पैमाने पर लाभ के निर्बाध वितरण को संभव बनाया है। स्व-पंजीकरण से लेकर भूमि स्वामित्व के सत्यापन और डीबीटी द्वारा समर्थ भुगतान तक, इस पूरी योजना का जीवनचक्र डिजिटल है।

राज्य सरकारों के सहयोग से, पीएम-किसान डिजिटल रूप से समन्वित तथा एक छोर से दूसरे छोर तक आसानी से पहुंचने वाले शासन के एक बेहतरीन मॉडल के रूप में कार्य करता है। इसने विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में भूमि अभिलेखों, लाभार्थियों के डेटाबेस और भुगतान प्रणालियों को सफलतापूर्वक समन्वित किया है औरइससे दुनिया के किसी भी अन्य देश की तुलना में किसान-केन्द्रित एक उत्तम संरचना का निर्माण हुआ है।

पीएम किसान ने कृषि से जुड़े इकोसिस्टम में किसान ई-मित्र वॉयस-आधारित चैटबॉट और एग्री स्टैक जैसी नवीन परियोजनाओं को भी प्रेरित किया है। एग्रीस्टैक व्यक्तिगत, समय पर और पारदर्शी सेवाएं प्रदान करने के लिए तैयार है, जिससे भारतीय कृषि भविष्य की जरूरतों के अनुरूप तैयार हो सके।

वैश्विक मानकों की स्थापना

दुनिया भर में, प्रत्यक्ष लाभ कार्यक्रमों को गरीबी उन्मूलन के कारगर साधनों के रूप में तेजी से मान्यता मिल रही है। फिर भी, पीएम-किसान की कुछ अनूठी विशेषताएं हैं –इसका विशाल आकार, गति और डिजिटल विश्वसनीयता इसे बिखरी हुई कृषि सहायता प्रणालियों में सुधार के लिए प्रयासरत देशों के लिए एक अनुकरणीय मॉडल बनाती है।

आईएफपीआरआई, एफएओ, आईसीएआर और आईसीआरआईएसएटीजैसी अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं ने छोटे किसानों की आय बढ़ाने, ऋण की सुलभता में सुधार, असमानता को कम करने और आधुनिक कार्यप्रणालियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने की दिशा में पीएम किसान की भूमिका पर प्रकाश डाला है। कई देशों में जारी सशर्त हस्तांतरण के उलट, इसका विश्वास-आधारित वबिना शर्त वाला दृष्टिकोण, सहभागी एवंसम्मान-आधारित कल्याणकारी वितरण की दिशा में एक बड़ी छलांग है।

ग्रामीण विकास को गति देना

पीएम-किसान का सकारात्मक प्रभाव केवल व्यक्तिगत लाभार्थियों तक ही सीमित नहीं है। इसके तहत होने वाले अनुमानित नकदी प्रवाह ने ग्रामीण बाजारों को पुनर्जीवित किया है, कृषि-उत्पादों की मांग को प्रोत्साहित किया है और घरेलू उपभोग के पैटर्न को मजबूत किया है। इसने महिलाओं को सशक्त बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, खासकर उन मामलों में जहांबैंक खाते संयुक्त रूप से खोले जाते हैं।

इसके अलावा, यह एक समग्र और परस्पर संबद्ध ग्रामीण विकास इकोसिस्टम का निर्माण करके मृदा स्वास्थ्य कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड, पीएम फसल बीमा योजना और ई-नाम जैसी अन्य प्रमुख योजनाओं का पूरक है। किसानों के लिए एक पेंशन योजना, पीएम-किसान मानधन योजना के साथ इसका एकीकरण, भारत के कृषि कार्यबल के लिए सामाजिक सुरक्षा जाल बनाने की दिशा में एक अहम कदम है।

सुनहरे भविष्य का एक दृष्टिकोणः दृढ़ता, समानता और स्थिरता

पीएम-किसान एक वित्तीय सहायता तंत्र से कहीं बढ़करहै। यह भारत सरकार के किसानों के नेतृत्व वाले विकास का एक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण है। अधिकार से सशक्तिकरण की ओर, सहायता से स्वायत्तता की ओर स्थानांतरित होकर, यह राज्य और किसान के बीच अनुबंध को नए सिरे से परिभाषित करता है।

भारत 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की आकांक्षा रखता है, ऐसे में पीएम-किसान जैसी पहल समावेशी प्रगति की नींव रखती है। उन्नत तकनीकों के निरंतर एकीकरण और जलवायु परिवर्तन के प्रति दृढ़ता, स्थिरता और सटीक कृषि पर ध्यान केंद्रित करने के साथ, यह योजना बदलाव की दिशा में एक बेहदशक्तिशाली कदमके रूप में विकसित होने के लिए तैयार है।

पीएम-किसान विश्वास, तकनीक और परिवर्तन की कहानी है। यह दुनिया के लिए भारत का योगदान है। यह योजना एक जीवंत उदाहरण है कि कैसे एक दूरदर्शी नीति, डिजिटल नवाचार और राजनीतिक इच्छाशक्ति के साथ मिलकर, लाखों लोगों को सशक्त बना सकती है और 21वीं सदी के शासन को नए सिरे से परिभाषित कर सकती है।

लेखक अतिरिक्त सचिव एवं अरिंदम मोदक, सलाहकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार हैं.

यह निजी विचार है।

विज्ञान को विषय नहीं, दृष्टिकोण बनाती 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020'

लेखकः डा मनमोहन प्रकाश, शिक्षाविद् एवं स्वतंत्र लेखन

÷तकनीकी दुनिया केवल कोडिंग से नहीं चलेगी, बल्कि उसे समझने के लिए गणित और भौतिकी की गहरी समझ जरूरी है।÷ यह कथन विश्व के तीन प्रतिष्ठित तकनीकी नेतृत्वकर्ताओं- जेन्सन हुआंग, एलन मस्क और पावेल डुरोव का है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस युग में, जब तकनीक मानव जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित कर रही है, तब इन हस्तियों का यह कथन इस बात की ओर संकेत करता है कि विज्ञान के मौलिक सिद्धांतों की समझ केवल वैज्ञानिकों के लिए ही नहीं, अपितु एक सामान्य नागरिक के लिए भी अत्यावश्यक होती जा रही है।

वर्तमान में जब भारत प्रगति के नए पथ पर है, एक चिंताजनक तथ्य उभर कर सामने आया है कि देश में गणित और भौतिकी जैसे बुनियादी विज्ञान विषयों को चुनने वाले छात्रों की संख्या में लगातार गिरावट देखी जा रही है। सीबीएसई के आँकड़ों के अनुसार, वर्ष 2020 की तुलना में 2024 में बारह प्रतिशत कम छात्रों ने इन विषयों को चुना। यह गिरावट न केवल एक शैक्षणिक आँकड़ा है, बल्कि यह भारत के वैज्ञानिक भविष्य के लिए एक चुनौती भी है।

इसी संदर्भ में यह प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठता है कि क्या भारत की 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020' वैज्ञानिक दृष्टिकोण को पुनर्जीवित करने और विद्यार्थियों को मौलिक विज्ञान की ओर आकृष्ट करने में सफल हो सकेगी? इस प्रश्न के उत्तर में अधिकांश शिक्षाविदों का मानना है कि यह नीति भारतीय शिक्षा प्रणाली में एक दूरदर्शी और ऐतिहासिक परिवर्तन की आधारशिला रखती है। इसका लक्ष्य केवल रोजगारोन्मुख शिक्षा प्रदान करना नहीं, बल्कि विद्यार्थियों को तार्किक, रचनात्मक और वैज्ञानिक सोच से युक्त नागरिक के रूप में विकसित करना है।

यह नीति अध्ययन को रटने की प्रक्रिया से निकालकर जिज्ञासा और प्रयोगशीलता की ओर ले जाती है। इसमें स्पष्ट उल्लेख है कि अधिगम की प्रक्रिया खोज, प्रश्न, चर्चा और विश्लेषण पर आधारित होनी चाहिए। यह सोच विज्ञान की आत्मा के अनुरूप है। आइंस्टीन का कथन ÷प्रश्न पूछना बंद न करें÷,इस नीति में साकार होता है। शिक्षा अब केवल ज्ञान-संचयन नहीं, बल्कि ज्ञान की जांच, प्रयोग और आत्मसात करने की प्रक्रिया है।

बच्चों में प्रयोग करने और स्वयं खोजने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने हेतु अटल नवाचार प्रयोगशालाएं, विज्ञान मेले, स्वनिर्मित परियोजनाएं और डिजिटल विज्ञान उपकरण जैसी योजनाएं शुरू की गई हैं। सी.वी. रमन ने कहा था, ÷विज्ञान का सार स्वतंत्र चिंतन है, न कि केवल उपकरण÷, और नीति इसी भावना को शिक्षा के केंद्र में लाने का प्रयास करती है।

नीति का एक विशेष पक्ष यह है कि विज्ञान की नींव प्रारंभिक कक्षाओं से ही रखी जाती है। कक्षा 6 से कोड लेखन, वैज्ञानिक गतिविधियाँ और परियोजना कार्य की व्यवस्था की गई है। बच्चों को आरंभ से ही प्रयोगात्मक अनुभव देना उन्हें जिज्ञासु और समस्या सुलझाने वाला बनाता है। डॉ. कलाम का कथन ÷अधिगम से सृजनशीलता, सृजनशीलता से चिंतन, चिंतन से ज्ञान और ज्ञान से महानता आती है÷,इस व्यवस्था में सजीव हो उठता है।

एक और क्रांतिकारी पहल यह है कि शिक्षा का माध्यम प्राथमिक कक्षाओं में मातृभाषा या स्थानीय भाषा हो, जिससे विद्यार्थी विज्ञान जैसे कठिन विषय को भी सहजता से समझ सकें। डॉ. जयंत नारलीकर का यह मत कि ÷विज्ञान तब ही सर्वसुलभ बनता है जब वह उस भाषा में पढ़ाया जाए जिसमें लोग सोचते हैं÷, नीति में प्रतिबिंबित होता है। यह बच्चों के आत्मविश्वास को बढ़ाने और विषय से डर को कम करने का भी माध्यम बनता है।

परीक्षा पद्धति में भी परिवर्तन किया गया है। अब मूल्यांकन केवल स्मृति की जांच नहीं, बल्कि अवधारणाओं की समझ, तर्क क्षमता और विश्लेषण पर आधारित होगा। नोबेल विजेता रिचर्ड फाइनमैन के अनुसार, ÷किसी वस्तु का नाम जानना और उसे समझना दो अलग बातें हैं।÷ यही समझ शिक्षा नीति की मूल भावना है।

नीति उच्च शिक्षा में अनुसंधान को भी विशेष महत्व देती है। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसंधान प्रतिष्ठान (नेशनल रिसर्च फाउंडेशन) की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया है, जो मौलिक विज्ञान में गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान को बढ़ावा देगा। मेघनाद साहा की चेतावनी÷वैज्ञानिक अनुसंधान विकासशील देशों की आवश्यकता है÷,इस नीति में पथदर्शक सिद्धांत की तरह है।

इसके साथ ही यह नीति विषयों की पारंपरिक सीमाओं को समाप्त करती है। अब विद्यार्थी अपनी रुचि के अनुसार विज्ञान, गणित, कला, संगीत, दर्शन आदि को एक साथ पढ़ सकते हैं। यह अंतरविषयक अध्ययन उन्हें जटिल समस्याओं का समग्र और रचनात्मक समाधान खोजने के लिए तैयार करता है। विज्ञान को प्रयोगशाला तक सीमित न रखते हुए, इसे जीवन के विविध क्षेत्रों में उपयोगी बनाने का यह प्रयास वस्तुतः ÷लेब से लैंड÷ की सार्थक यात्रा है।

जहाँ वैश्विक टेक्नोक्रेट्स मौलिक विज्ञान को भविष्य की तकनीकी क्रांति की रीढ़ मानते हैं, वहीं भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 विज्ञान को केवल एक विषय नहीं, बल्कि एक जीवन-दृष्टि के रूप में प्रस्तुत करती है। यह नीति विद्यार्थियों को जिज्ञासु, तार्किक, प्रयोगशील और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त नागरिक बनाने की दिशा में ठोस कदम है। यदि इसे पूरे देश में समन्वय के साथ, बिना राजनीतिक मतभेद के, निष्पक्ष रूप से लागू किया गया, तो यह भारत को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व प्रदान कर सकती है।

डॉ. होमी जहांगीर भाभा ने कहा था कि ÷भारत में विज्ञान का भविष्य केवल संस्थानों पर नहीं, बल्कि इस पर निर्भर करेगा कि हम युवाओं के मन में वैज्ञानिक चेतना कैसे उत्पन्न करते हैं।÷ यही वैज्ञानिक चेतना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की मूल आत्मा है और यही भारत के उज्ज्वल भविष्य की बुनियाद भी।

लेखक, स्तंभकार रायपुर छत्तीसगढ़,9009 415 415,

अर्थतंत्र से जुड़ी मानवीय विकास की पटकथा

नवीनता भी आवश्यक।

संजीव ठाकुर

वर्तमान समय में वैश्विक प्रगति और आर्थिक स्रोत तंत्र के लिए आधुनिक तथा वैज्ञानिक शिक्षा जरूर अत्यंत आवश्यक है। हमे केवल आधुनिक विचारधारा शिक्षा पद्धति पर निर्भर न रहकर अपनी सांस्कृतिक परंपराओं और सनातन संस्कृति के धरातल से जुड़ना होगा। तब जाकर सनातनी संस्कृत विचारधारा एवं आधुनिक वैज्ञानिक शिक्षा पद्धति का संतुलन यथोचित तरीके से हो पाएगा ।

भारत का सांस्कृतिक, सनातनी, वैदिक इतिहास सदैव गौरवपूर्ण रहा है। वेदों पुराणों और सनातनीं संस्कारों में इतनी शक्ति है कि भारतीय संस्कृति अनंत काल तक कभी नष्ट नहीं हो सकती है। भारतीय संस्कृति का लचीलापन एवं व्यापक ग्राह्यता इतनी विशाल है कि इस सभ्यता ने कई सभ्यताओं को अपने में समाहित कर एक विशाल धर्मनिरपेक्ष वातावरण तैयार किया है और वट वृक्ष की तरह अपनी शाखाएं वैश्विक स्तर पर प्रचारित, प्रसारित की है। यह वैदिक अध्यात्म योग और संस्कृति का ही प्रतिफल है कि भारत के नागरिक विश्व में चहुंओर निवास कर रहे हैं। अब समय आ गया है कि भारत को अपनी संस्कृति आध्यात्मिक तथा संस्कारों के आत्म बल के दम पर विश्व का नेतृत्व करना होगा एवं विश्व गुरु बनने की प्रक्रिया में नए नए सोपान निर्मित करने होंगे । प्रारंभ से ही शांति तथा मानवता को लेकर भारत में अपनी विकास यात्रा प्रारंभ की है आध्यात्मिक चिंतन और सनातनी इतिहास इस बात का गवाह है कि भारत विश्व शांति की बहाली के लिए विश्व को मार्गदर्शन देने का हौसला तथा क्षमता दोनों रखता है। अब यह समय आ चुका है कि भारत को विश्व का मार्गदर्शी प्रणेता बन जाना चाहिए।

जिंदगी का कैनवास जन्म से लेकर मृत्यु तक समुद्र की तरह विराट और गहराई लिए हुए होता है। जीवन में वयक्तिक, पारिवारिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, सामाजिक विकास की संभावनाओं के साथ मनुष्य अपना जीवन प्रारंभ कर विकास तथा ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकता है। बशर्ते उसके व्यक्तित्व में जीवन के प्रति जीजिविषा, संघर्ष करने की क्षमता, आत्म विश्वासके घटक मौजूद हों।

ऐतिहासिक तौर पर भारतीय विकास की सांस्कृतिक संरचना एवं संस्कार के मूलभूत तत्वों को लेकर दुनिया में अभूतपूर्व रही है। वैसे भी भारतवर्ष सभ्यता से लेकर संस्कृति के मामले में वैभवशाली इतिहास को समेटे हुए हैं। विकास और प्रगति के सोपान को एक दिन,वर्ष या दशक में रेखांकित नहीं किया जा सकता, यह एक निरंतर, सतत एवं समय के साथ चलने वाली क्रिया की प्रतिक्रिया है। प्रकृति सभ्यता तथा मानव जीवन में परिवर्तन एक अकाट्य सत्य और शाश्वत अभिक्रिया है। व्यक्ति के जीवन तथा समाज या देश में विकास के संदर्भ में एवं घटकों को प्रारंभ से आदमी का धन उपार्जन, गरीबी भुखमरी से लड़ाई भूतकाल की कुरीतियों की विडंबना से संघर्ष का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। किसी भी राष्ट्र के राजा, सम्राट या राष्ट्र प्रमुख की अपनी क्षमता ,शक्ति, ऊर्जा और उसके विवेक से उस राष्ट्र की प्रगति विशाल या न्यूनतम होती देखी गई है। भूतकाल में कई संघर्षशील एवं उत्साह से लबरेज यात्रियों के वृतांत हमारी नजरों में आए हैं यथा कोलंबस और वास्कोडिगामा जैसे अत्यंत ऊर्जावान संघर्षशील और साहसिक यात्रियों द्वारा लगभग नामुमकिन रास्तों की खोज कर एक मिसाल कायम की है। नेपोलियन का एक बड़ा सूत्र वाक्य था कुछ भी असंभव नहीं है। **यह निजी विचार है।**

औषधीय पौधों के संरक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर

पीआईबी

आयुष मंत्रालय के राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड (एनएमपीबी) ने औषधीय पौधों के संरक्षण से संबंधित आज दो महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। नई दिल्ली के निर्माण भवन में केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्री प्रतापराव जाधव की उपस्थिति में इन दोनों समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए।

पहले समझौता ज्ञापन पर राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड (एनएमपीबी) और पुणे, महाराष्ट्र के ईश वेद-बायोप्लांट्स वेंचर ने हस्ताक्षर किए। दूसरे त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड (एनएमपीबी), अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (एआईआईए) और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), नई दिल्ली के बीच हस्ताक्षर किए गए। श्री जाधव ने इस अवसर पर अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी

का 2047 तक एक स्वस्थ और आत्मनिर्भर भारत बनाने का दृष्टिकोण हमारे प्रयासों में मार्गदर्शक है। उन्होंने समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करने वाले संस्थानों को बधाई देते हुए कहा कि ये समझौते भारत की समृद्ध औषधीय पादप विरासत संरक्षण और संवर्धन में महत्वपूर्ण साबित होंगे। उन्होंने कहा कि हम पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक विज्ञान के साथ समेकित कर प्रधानमंत्री के महत्वाकांक्षी दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में सार्थक प्रगति कर रहे हैं।

दोनों समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर के उद्देश्य : राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड (एनएमपीबी) और ईश वेद-बायोप्लांट्स वेंचर के बीच समझौता ज्ञापन का उद्देश्य ऊतक संवर्धन विधियों से दुर्लभ, लुप्तप्राय और संकटग्रस्त औषधीय पौधों के जर्मप्लाज्म (पौधों और जीवों की आनुवांशिक संरचना सामग्री) का संरक्षण और रखरखाव करना है। इससे आयुष उद्योग में प्रयुक्त दुर्लभ, लुप्तप्राय और संकटग्रस्त श्रेणी के औषधीय पौधों की आपूर्ति सुगमता के लिए ऊतक संवर्धन विधियों के विकास और उनकी व्यापक खेती एवं रखरखाव द्वारा हितधारकों को बेहतर मूल्य प्राप्त होगा और इन औषधीय पौधों के जर्मप्लाज्म को संरक्षित रखा जा सकेगा। समझौते में दोनों पक्ष औषधीय पादप क्षेत्र और आयुष उद्योग के विकास तथा लाभ के लिए अपनी विशेषज्ञता और संसाधनों के उपयोग हेतु सहयोग के क्षेत्रों की पहचान करेंगे। राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड (एनएमपीबी), अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (एआईआईए) और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के बीच हुए दूसरे समझौता ज्ञापन में नई दिल्ली के एम्स परिसर में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान द्वारा औषधीय पौध उद्यान की स्थापना की जाएगी और औषधीय पौधों के बारे में जन जागरूकता फैलाई जाएगी।

संन्तों के आशीर्वाद से पुण्य मिलता है: भाई मुकेश

एजेंसी - केसिंगा आचार्य महाश्रमण जी के सू शिष्य मुनी श्री जीनेश कुमार जी के सानिध्य में केसिंगा तेरापंथ सभा का एक प्रतिनिधि मंडल हावड़ा के पूर्व अंचल पे विराजित मुनी श्री जीनेश कुमार जी के दर्शनार्थ पहुंच रहे हैं। वहां पर विराजित मुनी श्री परमान्द जी एवं सबके चाहते मुनी श्री कुणाल कुमार जी का दर्शन करने के लिए हावड़ा की ओर जा रहे हैं।मुनि श्री जी का करीबन 4 साल पहले केसिंगा में चातुर्मास सादर संपन्न करते हुए हावड़ा पहुंचे थे ।वहां पर विगत 3 वर्षों से मुनिश्री जी का चतुर्मास चल रहा है । इस प्रतिनिधि मंडल में केसिंगा सभा के अध्यक्ष श्री राम कुमार जैन पूर्व अध्यक्ष मंगतराम जैन , स्थानीय सभा के महासचिव नंन्दकिशोर जैन, संतोष जैन,कमल जैन, विनोद जैन, स्थानीय महिला मंडल की ओर से पिंन्की जैन भी साथ में जा रहे हैं ,प्रांतीय तेरापंथ महासभा के पूर्व अध्यक्ष श्री मुकेश जैन, प्रांतीय तेरापंथ सभा के महासचिव श्री सुदर्शन जैन , प्रांतीय महासभा के उप सचिव श्री सुनील जैन इन साथियों ने हर्ष और उल्लास के साथ यात्रा कर रहे हैं। बलांगीर से लेकर के झारसुगुड़ा तक सभी के रिश्तेदारों ने जलपान की बहुत ही सुंदर व्यवस्था कर रखी थी । सभी ने आनंद के साथ जलपान ग्रहण किया। मुनि श्री जी का जहां भी चातुर्मास लगता है वहां पर ठाठ लग जाता है। उनसे आशीर्वाद लेने के लिए प्रशासनिक अधिकारी एवं राजनेता भारी संख्या में आते जाते रहते हैं

प्रयागराज में मानसून के मौसम में गंगा नदी के जलस्तर में वृद्धि के बीच एसडीआरएफ के जवान बाढ़ग्रस्त क्षेत्र से लोगों को निकालते हुए।

चमोली में बारिश के बाद बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग अवरुद्ध होने से वाहन फंसे हुए हैं।

पूर्वोत्तर और दक्षिणी भारत के बीच अंतर-सांस्कृतिक पर्यटन

पीआईबी

नागरिक उड्डयन मंत्रालय (एमओसीए) ने देश में असेवित और अल्पसेवित हवाई अड्डों से क्षेत्रीय हवाई संपर्क बढ़ाने और आम जनता के लिए हवाई यात्रा को किफायती बनाने के लिए 21 अक्टूबर 2016 को क्षेत्रीय संपर्क योजना 'उड़े देश का आम नागरिक (आरसीएस-उड़ान)' शुरू की। इस योजना के अंतर्गत, पर्यटन संपर्क को मज़बूत करने के उद्देश्य से, पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) और दक्षिण भारत सहित देश भर में 53 पर्यटन आरसीएस मार्ग पर्यटन - आरसीएस (टीआरसीएस) के अंतर्गत संचालित किए जा रहे हैं। इन मार्गों को पर्यटन मंत्रालय द्वारा 100 प्रतिशत व्यवहार्यता अंतर निधि (वीजीएफ) प्रतिपूर्ति से वित्त पोषित किया गया है, जिससे देश के पर्यटन स्थलों और सांस्कृतिक स्थलों तक सीधी हवाई संपर्क सुविधा उपलब्ध हुई है। यद्यपि आरसीएस उड़ान के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र के हवाई अड्डों और दक्षिण भारतीय हवाई अड्डों के बीच कोई सीधी हवाई संपर्क सुविधा नहीं है, फिर भी कनेक्टिंग उड़ानों के माध्यम से अप्रत्यक्ष संपर्क सुविधा उपलब्ध है। क्षेत्रीय संपर्क योजना (आरसीएस-उड़ान) के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) में कुल 90 मार्ग चालू किए गए हैं, जो पूर्वोत्तर राज्यों में 10 हवाई अड्डों और 2 हेलीपोर्ट को जोड़ते हैं।

भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम ने बताया है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में थीम-आधारित सर्किट पर भारत गौरव ट्रेनों की कुल 17 यात्राएँ संचालित की गईं, जिनमें 9,246 पर्यटकों ने तमिलनाडु का भ्रमण किया।

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से अब तक 4.05 करोड़ महिलाओं को लाभ

पीआईबी

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) के लिए विशेष पंजीकरण अभियान की अवधि 15 अगस्त, 2025 तक बढ़ा दी है। आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में घर-घर जाकर जागरूकता एवं नामांकन अभियान का उद्देश्य सभी पात्र गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं तक पहुंचना और योजना के तहत उनका समय पर पंजीकरण सुनिश्चित करना है। पीएमएमवीवाई गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं (पीडब्लूएंडएलएम) के बीच पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने और स्वास्थ्य संबंधी व्यवहार में सुधार लाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है और बालिकाओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देती है।

पीएमएमवीवाई वेतन में कमी होने की स्थिति में आंशिक मुआवजे के रूप में नकद प्रोत्साहन प्रदान करती है ताकि माताएं पहले बच्चे के जन्म से पहले और बाद में आराम कर सकें। इस योजना की शुरुआत से लेकर 31 जुलाई, 2025 तक 4.05 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को उनके बैंक/डाकघर खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के

माध्यम से 19,028 करोड़ रूपये की राशि का मातृत्व लाभ (कम से कम एक किस्त) का भुगतान किया जा चुका है।

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, मिशन शक्ति की उप-योजना 'सामर्थ्य' के अंतर्गत एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जो प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्रदान करती है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत, मिशन शक्ति योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, पहली संतान के लिए दो किस्तों में 5,000 रूपये और दूसरी बालिका के जन्म के बाद एक किस्त में 6,000 रूपये की नकद प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। इस योजना का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं में स्वास्थ्य संबंधी व्यवहार में सुधार लाना और देश भर में बेहतर मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सुनिश्चित करना है।

इस योजना का कार्यान्वयन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारियों द्वारा अपने क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं के माध्यम से नए प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना सॉफ्टवेयर का उपयोग करके किया जाता है, जिसे मार्च, 2023 में लॉन्च किया गया था। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना सॉफ्टवेयर के तहत, यूआईडीएआई के माध्यम से आधार प्रमाणीकरण डिजिटल रूप से किया जाता है और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा सत्यापन सुनिश्चित किया जाता है ताकि धनराशि सीधे उनके डीबीटी-सक्षम आधार-सीडेड बैंक या डाकघर खातों में स्थानांतरित की जा सके। योजना के सुचारू वितरण और व्यापक कवरेज को सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना पोर्टल में एकीकृत शिकायत मॉड्यूल, बहुभाषी और टोल-फ्री प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना हेल्पलाइन (14408), चेहरे की पहचान प्रणाली का उपयोग करके आधार-समर्थित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की संभावित लाभार्थियों की सूची आदि जैसे कई सुधार किए गए हैं।

'स्वदेश दर्शन योजना 2.0' में उभरते पर्यटन रुझानों को समावेशन

पीआईबी

पर्यटन मंत्रालय ने देश में चिन्हित विषयगत पर्यटन सर्किटों के अंतर्गत पर्यटन अवसंरचना विकसित करने के उद्देश्य से वर्ष 2014-15 में 'स्वदेश दर्शन योजना (एसडीएस)' आरंभ की थी। इस 'स्वदेश दर्शन 2.0 (एसडी2.0)' योजना को नया रूप दिया गया है जिसका उद्देश्य पर्यटन और गंतव्य केंद्रित दृष्टिकोण के साथ स्थायी पर्यटन स्थलों का विकास करना है और इसने 52 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन की एक उप-योजना 'चुनौती आधारित गंतव्य विकास (सीबीडीडी)' के अंतर्गत 36 परियोजनाओं को भी मंजूरी दी है। सरकार ने 'पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता (एसएएससीआई)' योजना के अंतर्गत देश में 40 परियोजनाओं को भी मंजूरी दी है। उपर्युक्त योजना के अंतर्गत परियोजनाओं को राज्यों से परियोजना प्रस्ताव प्राप्त होने, उसके मूल्यांकन, धन की उपलब्धता, पारस्परिक प्राथमिकता आदि के आधार पर मंजूरी दी गई।

'स्वदेश दर्शन 2.0' योजना इस बात को मान्यता देती है कि नकारात्मक प्रभावों को न्यूनतम करने और सकारात्मक प्रभावों को अधिकतम करने के लिए, सतत और उत्तरदायी पर्यटन अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह पर्यावरणीय स्थिरता, सामाजिक-सांस्कृतिक स्थिरता और आर्थिक स्थिरता सहित सतत पर्यटन के सिद्धांतों को अपनाने को प्रोत्साहित

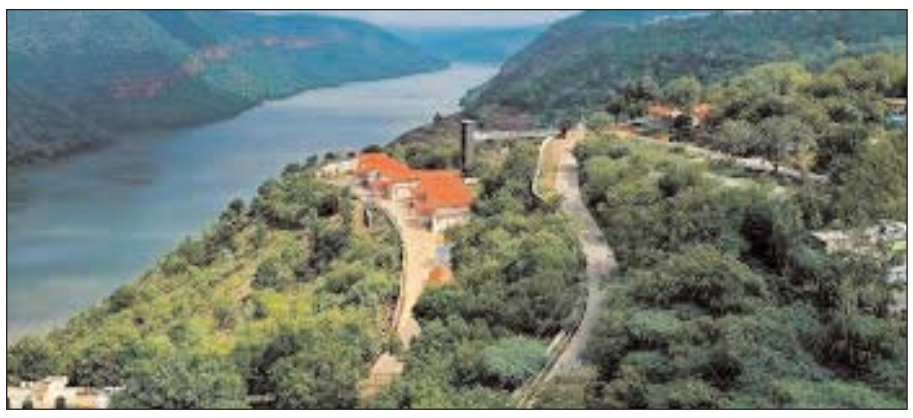

करती है। यह योजना पर्यटकों को बेहतर अनुभव प्रदान करने के लिए नए उभरते रुझानों सहित विविध पर्यटन परियोजनाओं के विकास पर केंद्रित है। स्वदेश दर्शन योजना में उभरते रुझानों को शामिल करने के लिए कोई विशिष्ट अध्ययन नहीं किया गया है। योजना के दिशानिर्देश उन घटकों की एक विस्तृत सूची प्रदान करते हैं जो पर्यटन की संभावनाओं को बढ़ा सकते हैं, जिनमें पर्यटन के मुख्य उत्पाद, पर्यटन गतिविधियां, प्रदर्शन कला अवसंरचना, स्वच्छता एवं सुरक्षा, संपर्क एवं पार्किंग, सामान्य स्थल विकास, सॉफ्ट इंटरवेंशन आदि शामिल हैं। स्वदेश दर्शन 2.0, सीबीडीडी और एसएएससीआई योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं में विभिन्न पर्यटन रुझान और समुद्र तट अनुभव, गुफा अनुभव, साहसिक कार्य, सीमा अनुभव, ध्यान केंद्र, सम्मेलन केंद्र, धार्मिक एवं आध्यात्मिक पहलू, पक्षी अभयारण्य, ऐतिहासिक थीम पार्क, आदिवासी संस्कृति अनुभव, किला, जैव-विविधता और पर्यावरण-मनोरंजन, पनडुब्बी पर्यटन आदि जैसे गहन अनुभव शामिल हैं।

मंत्रालय बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए अपनी योजनाओं के अंतर्गत सभी के लिए सम्पर्क सुविधा भी प्रदान करता है। मंत्रालय सड़क और हवाई संपर्क सहित कनेक्टिविटी में सुधार के लिए संबंधित मंत्रालयों के साथ समन्वय करता है।

नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने देश के कम और कम सेवा वाले हवाई अड्डों से क्षेत्रीय हवाई संपर्क बढ़ाने और आम जनता के लिए हवाई यात्रा को किफायती बनाने के लिए 21 अक्टूबर 2016 को क्षेत्रीय संपर्क योजना ङ्क 'उड़े देश का आम नागरिक (आरसीएस-यूडीएएन)' शुरू की है। उड़ान योजना के अंतर्गत तीसरे दौर की बोली के दौरान, पर्यटन मंत्रालय के अनुरोध पर कुल 106 पर्यटन-विशिष्ट मार्गों को शामिल किया गया।

पर्यटन मंत्रालय द्वारा 100 प्रतिशत वीजीएफ समर्थन के साथ उड़ान के अंतर्गत 31 जनवरी 2025 तक कुल 53 पर्यटन आरसीएस मार्ग संचालित किए गए जो देश के पर्यटन स्थलों और सांस्कृतिक स्थलों के लिए सीधा हवाई संपर्क प्रदान करते हैं। सरकार ने देश भर में 120 नए गंतव्यों तक क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने और अगले 10 वर्षों में 4 करोड़ यात्रियों की सेवा करने के लिए संशोधित उड़ान योजना शुरू करने की भी घोषणा की है। यह योजना पहाड़ी, आकांक्षी और पूर्वोत्तर क्षेत्र के जिलों में हेलीपैड और छोटे हवाई अड्डों के निर्माण में भी मदद करेगी।

मंत्रालय ने देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, प्राकृतिक सौंदर्य और विविध आकर्षणों को देखने में रुचि रखने वाले यात्रियों और हितधारकों के लिए एक व्यापक संसाधन के रूप में अतुल्य भारत डिजिटल प्लेटफॉर्म (आईआईडीपी) का नया संस्करण लॉन्च किया है। भारत डिजिटल प्लेटफॉर्म एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआइ)-संचालित टूल का उपयोग करता है जो वास्तविक समय के मौसम अपडेट, शहर की खोज और आवश्यक यात्रा सेवाएं प्रदान करके आगंतुकों के अनुभव को वैयक्तिकृत करता है।

स्कूली विद्यार्थियों के बीच भारतीय शास्त्रीय नृत्यों को प्रोत्साहन देना

भारत सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी)-2020 के उद्देश्यों के अनुरूप, भारतीय पारंपरिक नृत्यों के विभिन्न रूपों को स्कूली शिक्षा ढांचे में एकीकृत करने के लिए कदम उठाए हैं।

एनईपी-2020 एक अंतर-पाठ्यक्रम शैक्षणिक दृष्टिकोण के रूप में कला-एकीकृत शिक्षा का समर्थन करती है। यह पारंपरिक नृत्य जैसी भारतीय कलाओं को मुख्यधारा की कक्षा शिक्षा में शामिल करने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह विद्यार्थियों में रचनात्मकता, सांस्कृतिक जड़ता और समग्र विकास को प्रोत्साहन देने के लिए शिक्षा के सभी स्तरों पर भारतीय कलाओं के महत्व पर बल देती है।

संस्कृति मंत्रालय ने इस उद्देश्य से अपने स्वायत्त संगठन संगीत नाटक अकादमी के माध्यम से कला धरोहर श्रृंखला शुरू की है। इसे विशेष रूप से स्कूली विद्यार्थियों के बीच शास्त्रीय नृत्य सहित भारतीय प्रदर्शन कलाओं के प्रति जागरूकता और प्रशंसा को बढ़ावा देने के लिए तैयार किया गया है।

संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत अन्य निकाय, जैसे सांस्कृतिक संसाधन एवं प्रशिक्षण केन्द्र (सीसीआरटी) भी इन लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए पूरे देश के स्कूलों में कार्यशालाएं, अभिविन्यास कार्यक्रम और सांस्कृतिक गतिविधियां आयोजित करते हैं, जो भारतीय कला और संस्कृति को प्रोत्साहन देने में योगदान देते हैं।

भारत सरकार अपने स्वायत्त निकाय सांस्कृतिक संसाधन एवं प्रशिक्षण केंद्र (सीसीआरटी) के माध्यम से अनेक, विविधतापूर्ण और समृद्ध भारतीय सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करती है। सांस्कृतिक प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति योजना, सीटीएसएसएस (10-14 वर्ष) के माध्यम से सीसीआरटी 1982 से विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों जैसे संगीत, नृत्य, नाटक के पारंपरिक रूपों के साथ-साथ चित्रकला, मूर्तिकला, शिल्प और साहित्यिक गतिविधियों में विशेष प्रशिक्षण प्रदान करता है।

लोकशक्ति www.lokshakti.in

बर्मा के श्वेत मंदिर की प्रतिकृति के बने पंडाल में विराजेंगी मां 140 फीट ऊंचा और 150 फीट चौड़ा भव्य प्रवेश द्वार रहेगा

आकर्षण का केंद्र, पंडाल और प्रतिमा हो रही तैयार...

जांजगीर-चांपा -

नैला जांजगीर में दुर्गा पूजा उत्सव मनाने की तैयारी जोर-शोर से शुरू की जा रही है। इस बार म्यांमार देश के सुप्रसिद्ध श्वेत मंदिर की प्रतिकृति का 140 फीट ऊंचा और 150 फीट चौड़ा भव्य प्रवेश द्वार आकर्षण का केंद्र रहेगा। समिति के लोगों ने इसके लिए अभी से तैयारी करना शुरु कर दी है। श्रीश्री दुर्गा पूजा उत्सव सेवा समिति नैला के अध्यक्ष राजू पालीवाल ने बताया कि नैला का दुर्गा उत्सव इस वर्ष भी जिला और प्रदेश ही नहीं बल्कि देशभर में चर्चित होगा। इस बार नैला के विशाल पांडाल में विश्व प्रसिद्ध श्वेत मंदिर की प्रतिकृति में भव्य पंडाल बनाया जाएगा। पंडाल सहित मां दुगां प्रतिमा बनाने का काम शुरू हो गया है। नैला की मां दुर्गा की प्रतिमा और भव्य प्रवेश द्वार हर साल प्रदेश ही नहीं देशभर में प्रसिद्धि के

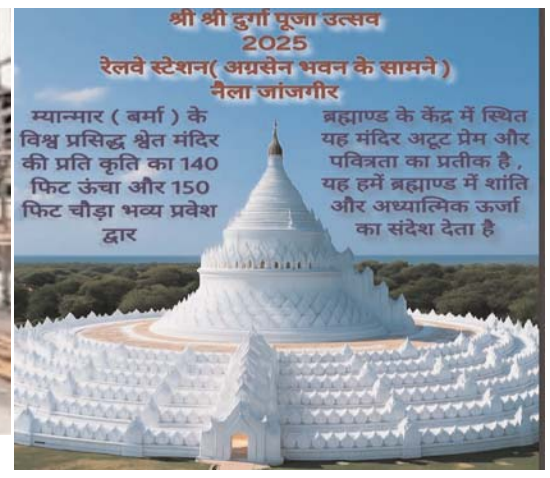

लायक रहता है।

मां दुर्गा की 35 फीट ऊंची रत्नजड़ित प्रतिमा..... श्रीश्री दुर्गा पूजा उत्सव सेवा समिति के अध्यक्ष राजू पालीवाल ने बताया कि पंडाल के भीतर मां दुर्गा की 35 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी, जो हीरे, मोती और रत्नों से अलंकृत होगी। इस भव्य प्रतिमा की पृष्ठभूमि अक्षरधाम मंदिर के गुंबदों और शीतमहल की शैली में निर्मित की जाएगी, जो एक दिव्य आभा प्रदान करेगी। यह नइनाभिराम दृश्य भक्तों को एक अलौकिक लोक का अनुभव कराएगा।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सजी लेजर लाइटिंग और संगीत की झंकार....

इस बार की दुर्गा पूजा में अतरराष्ट्रीय कलाकार द्वारा प्रस्तुत विशेष लेजर शो और लाइटिंग प्रभाव का समावेश किया गया है, जिसमें आध्यात्मिक संगीत और प्रकाश की लहरे श्रद्धालुओं को एक दिव्य यात्रा पर ले जहांगी। यह तकनीकी संयोजन बढ़ा के साथ संरकृति का अनूठा संगम प्रस्तुत करेगा।

सुरक्षा, स्वच्छता और सेवा की त्रिवेणी.... श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा की प्राथमिकता देते हुए आयोजन समिति ने विशेष प्रबंध किए है। डिजिटल निगरानी, स्वच्छता व्यवस्था, वालिंटियर सहायता केंद्र और चिकित्सा आपातकालीन सेवा चौबीसों घंटे उपलब्ध रहेंगी, ताकि हर आगंतुक को सुरक्षित अनुभव मिल सके।

पूजा पंडाल के निर्माण में पश्चिम बंगाल के विशेष कारीगरों के साथ-साथ स्थानीय कलाकारों का समावेश किया गया है, जो पारंपरिक और आधुनिक कला के संगम

को जीवंत कर रहे हैं। डोम हाल की सजावट इस बार विशेष रूप से बर्मा की वास्तुकला और भारतीय पारंपरिक शिल्प कला का मिश्रण होगी।

पेंशनर कल्याण संघ ने सौंपा ज्ञापन

जांजगीर चांपा /

छत्तीसगढ़ प्रदेश के पेंशनरों का लंबित 02प्रतिशत मंहगाई भत्ता,धारा 49(6) हटाने, संघ को प्रचार की मान्यता देने, छग पेंशनर कल्याण मंडल का गठन करने, पेंशनरों को 3000मेडिकल भत्ता देने कैशलैस चिकित्सा सुविधा देने सहीत 11 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन मुख्यमंत्री छग के नाम अतिरिक्त कलेक्टर बिलासपुर एस के बनर्जी को सौंपा गया। प्रतिनिधि मंडल में छग प्रगतिशील पेंशनर कल्याण संघ के प्रदेश अध्यक्ष आर के थवाईत, महामंत्री सुंदर सिंह ठाकुर, महिला प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती पुष्पा मिश्रा, संयुक्त सचिव सी पी मिश्रा ,महेश साव उपस्थित रहे।

भगवान को जो प्रिय नही वह धर्म नही – स्वामी रामकृष्णाचार्य महराज जी पत्रकारों से हुए रूबरू

लोकशक्ति जांजगीर चांपा /

शहर के अग्रसेन भवन में तीन से सात अगस्त तक श्री वेंकटेश झूला उत्सव कार्यक्रम का आयोजन बसईवाल परिवार द्वारा किया जा रहा है । इसे लेकर आज सोमवार सात अगस्त को मध्य प्रदेश के इटारसी से पहुंचे स्वामी रामकृष्णचार्य ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि मर्यादा का पालन कर भगवान की भक्ति करनी चाहिए जो भगवान को प्रिय नहीं वह धर्म नहीं हो सकता ।

पत्रकारों के द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में आचार्य ने कहा कि महिलाओं को व्यास पीठ पर बैठने की अनुमति वेद नहीं देता लेकिन वे आपस में बैठकर कीर्तन भजन सत्संग कर सकते हैं। धर्मांतरण को लेकर उन्होंने कहा कि इसके लिए लोगों को स्वयं सजग एवं सचेत रहना चाहिए , आगे उन्होंने कहा कि राजनीति एवं धर्म एक ही है और धर्म का पालन करते हुए राजनीति करनी चाहिए एवं प्रजा का पालन अपने बेटे की तरह करना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोगों को माता शबरी का अनुसरण करते हुए भक्ति एवं प्रेम के साथ भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए ।

पत्रकार के द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में महाराज जी ने कहा कि व्यास पीठ पर बैठने का अधिकार ब्राह्मणों को ही है वहीं उन्होने साई बाबा के विषय में भी दो टूक कहा कि सनातन धर्म में इसका उल्लेख कहीं नही है इसलिए सनातन धर्मावलंबियों को इससे दूर रहना चाहिए । इस दौरान झूला महोत्सव आयोजक परिवार से कैलाश बसईवाल , पवन अग्रवाल, देवेश बसईवाल , अंकित बसईवाल, आनंद बसईवाल, पंकज अग्रवाल , अशोक गोयल , धन्नू गट्टानी सहित पारिवारिक जन उपस्थित रहे ।

सुबह प्रवचन के साथ रात्री झूला उत्सव - इस आयोजन में प्रतिदिन सुबह 10 बजे से लेकर 12.30 तक स्वामी रामकृष्णाचार्य जी के श्रीमुख से प्रवचन सत्संग का कार्यक्रम होता है, वहीं रात्री 7.30 से 11 बजे तक झूला उत्सव का कार्यक्रम होता है जिसके लिए 300 कार्यकर्ता स्वामी जी के साथ बाहर से पहुंचे हुऐ हैं।

अलग अलग जगहों से अवैध शराब बिक्री के तीन आरोपियों को किया गिरफ्तार

आरोपियों के कब्जे से 14 लीटर अवैध कच्ची महुआ एवं 37 पाव देशी प्लेन शराब जब्त

जांजगीर चांपा / अलग अलग जगहों से अवैध शराब बिक्री के तीन आरोपीयों को गिरफ्तार किया गया है। ज्ञात हो कि पुलिस अधीक्षक जांजगीर चांपा विजय कुमार पाण्डेय आईपीएस के निर्देशन में जिले में अवैध शराब बिक्री पर अंकुश लाने के लिए जिला पुलिस जांजगीर द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है । इसी क्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश कश्यप के मार्गदर्शन में अवैध शराब बिक्री करने वालों के विरुद्ध रेड कार्यवाही किया गया जिसमें थाना पामगढ़ पुलिस द्वारा आरोपी प्रदीप रात्रे उम्र 44 वर्ष साकिन भैंसो नवापारा थाना पामगढ़ के कब्जे से 8 लीटर अवैध कच्ची महुआ शराब , थाना चांपा पुलिस द्वारा आरोपी संतोष कुमार राठौर उम्र 48 साल निवासी कोसमंदा के कब्जे से 33 पाव देशी प्लेन शराब एवं परिवहन में प्रयुक्त एक

स्कूटी ,थाना नवागढ़ पुलिस द्वारा आरोपी दीपक लहरें उम्र 27 साल निवासी केरा थाना नवागढ़ के कब्जे से 6.15 लीटर अवैध कच्ची महुआ शराब एवं 04 पाव देशी प्लेन शराब बरामद किया जाकर आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। उपरोक्त कार्यवाही में निरीक्षक अशोक वैष्णव थाना प्रभारी नवागढ़, निरीक्षक जेपी गुप्ता थाना प्रभारी चांपा, उपनिरी मनोहर सिन्हा थाना प्रभारी पामगढ़ का सराहनीय रहा।

दशमी तिथि पर याद किए गए श्री महन्त लाल दास जी महाराज नगर के विप्रजन के लिए हुआ ब्राह्मण भोज का आयोजन

जांजगीर चांपा / शिवरीनारायण मठ के पूर्वाचार्य श्री महन्त लाल दास जी महाराज को श्रावण शुक्ल दशमी तिथि पर याद किया गया। उनकी पुण्य स्मृति में परंपरागत रूप से ब्राह्मण भोजन का आयोजन किया गया जिसमें नगर के सभी विप्रजन सम्मिलित हुए। इस अवसर पर भगवान की विशेष पूजा अर्चना की गई। भोग प्रसाद बनाने में महामंडलेश्वर राजेश्री महन्त रामसुन्दर दास जी महाराज ने स्वयं हाथ बटाया। दोपहर 12:30 बजे भगवान की विशेष पूजा अर्चना की गई। सभी ब्राह्मणों को भोजन के पश्चात तिलक लगाकर विदाई दी गई। इस कार्यक्रम में संत श्री रामगोपाल दास जी महाराज विशेष रूप से उपस्थित हुए। अपने संदेश में राजेश्री महन्त जी महाराज ने कहा कि -श्री महन्त लाल दास जी महाराज शिवरीनारायण मठ के पूर्वाचार्य थे। श्रावण शुक्ल दशमी को वे परलोक सिधार गए तब से उनकी स्मृति में

शिवरीनारायण मठ में प्रत्येक वर्ष निर्धारित तिथि पर भोग भंडारा का आयोजन होता है, जिसमें नगर के सभी विप्र जन उपस्थित होते हैं। उन्होंने कहा कि यह सेवा का कार्य है जो परंपरागत रूप से संचालित हो रहा है। भोग भंडारा तैयार करने में सुखराम दास जी, त्यागी जी महाराज, चित्रकूट से पधारे हुए महात्मा जी एवं अनेक संत महात्माओं तथा मठ मंदिर के विद्यार्थियों ने सेवा का कार्य पूर्ण करने में सहयोग प्रदान किया। इस अवसर पर विशेष रूप से मठ मंदिर ट्रस्ट कमेटी के सदस्य बृजेश के सरवानी, राघवेंद्र प्रताप सिंह तथा निरंजन लाल अग्रवाल, पूर्णेन्द्र तिवारी, मीडिया प्रभारी निर्मल दास वैष्णव, ज्ञानेश शर्मा, पुरेंद्र सोनी सहित अनेक गणमान्य नागरिक गण उपस्थित थे। सेवा कार्य पूर्ण करने में राम तीरथ दास जी, राजीव त्रिपाठी, टुकाराम वर्मा, गणेश नेताम, भुजंगा, अंकित दुबे, दाऊराम साहू आदि के नाम उल्लेखनीय हैं।

बटनदार चाकू की नोक से धमकी के आरोपी गिरफ्तार

जांजगीर चांपा / बटनदारचाकू की नोक से धमकी के आरोपी को चांपा पुलिस ने गिरफ्तार किया है । मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 3 अगस्त 25 को रात्रि करीबन 11 बजे के आसपास प्रार्थी विनोद कुमार निवासी चरण नगर चांपा अपने घर के पास बाहर में था तभी आरोपी द्वारा पुरानी रंजिश को लेकर गाली

गलौच करते हुए रात में चाकू लेकर प्रार्थी को मारने के लिए डराने धमकाने हुए दौड़ाया तो डर से घर के अंदर चला गया । उक्त सूचना रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया और आरोपी को घेराबंदी कर पकड़ा जिसके कब्जे से चाकू बरामद करने के साथ विधिवत् गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में भेजा गया। उपरोक्त कार्यवाही मे निरीक्षक जय प्रकाश गुप्ता, उप निरी. उमेंद्र मिश्रा, आर सुमंत कंवर, शंकर सिंह राजपूत, प्रहलाद दिनकर, आकाश कलोशिया का सराहनीय योगदान रहा।

ऑपरेशन मुस्कान के चलाया गया विशेष अभियान

59 अपहृत , गुम बालक बालिकाओं को खोज निकालने में मिली सफलता

जांजगीर चांपा / पुलिस मुख्यालय रायपुर के निर्देशन में माह जुलाई 2025 में आपरेशन मुस्कान चलाकर अधिक से अधिक अपहृत ,गुम बालक बालिका को बरामद करने निर्देशित किया गया था। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पाण्डेय आईपीएस के द्वारा जिले में गुम- अपहृत बालक बालिका की बरामदगी हेतु थाना चौकी प्रभारियों को सख्त निर्देशित कर उचित कार्यवाही करने निर्देशित किया गया था। इसी कड़ी में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश कुमार कश्यप के कुशल मार्गदर्शन में जिला पुलिस जांजगीर -चाम्पा द्वारा गुम इंसान एवं अपृहत बालक बालिकाओं की दस्तयाबी हेतु माह जुलाई 2025 एक माह तक विशेष अभियान चलाया गया। जिले में गुम बालक बालिका दस्तायाब हेतु थाना चौकी स्तर पर टीमों का गठन किया गया था। गठित टीमों के द्वारा हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर, बिहार, आंध्र प्रदेश तरफसे तथा छ.ग. के अलग- अलग जिलों से कुल 59 अपहृत गुम बालक - बालिकाओं को सकुशल बरामद कर दस्तायाब किया जाकर उनके परिजनो को सकुशल सुपूर्द किया गया है। इस प्रकार जिले के गुम अपहृत 11 बालक एवं 48 बालिका को सकुशल बरामद कर उनके परिजनों को सुपूर्द किया गया तथा प्रकरण में अग्रिम वैधानिक कार्यवाही जी जा रही है।

पॉवर कंपनी के वित्त प्रबंधन में बढ़ाया जाये एआई का उपयोग

रायपुर। छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर कंपनीज डंगनिया मुख्यालय में ÷एआई फॉर फाइनेंस एक्जीक्यूटिव ÷विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। पॉवर कंपनी में ''आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस'' का उपयोग बढ़ाने के लिए वित्तीय अधिकारियों को दक्ष, जागरूक और स्वप्रेरित होना चाहिए ताकि नये जमाने के नये आवश्यकताओं का लाभ वित्त प्रबंधन में भली भांति मिल सकें। उक्त आशय के विचार एमडी(जेनको) श्री एसके कटियार ने आज की कार्यशाला में व्यक्त किए।

इस अवसर पर एमडी(ट्रांस्को) श्री राजेश कुमार शुक्ला ने कहा कि नई परियोजनाओं में एआई के उपयोग से बेहतर शोध किये जा सकते हैं । वित्तीय प्रबंधन को कारगर बनाया जा सकता है और जटिल प्रक्रियाओं का सरलीकरण किया जा सकता हैं। कार्यशाला में मुख्य वक्ता चार्टर्ड एकाउंटेंट श्री करण गुप्ता ने एआई के उपयोग के लिये विभिन्न माध्यमों और प्रक्रियाओं के बारे में बताया । वित्तीय प्रबंधन के लिए पूर्वानुमान- विश्लेषण, डेटा संकलन, प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं के लिए वैश्विक मापदंडों व स्थानीय जरूरतों आदि विषयों सटीक डेटा संग्रह व विश्लेषण पर पॉवर पांइट के माध्यम से प्रस्तुति दी। कार्यशाला में उपस्थित वित्त अधिकारी एवं कर्मचारियों ने प्रश्नोत्तर सत्र में इस टूल के उपयोग और चुनौतियों पर चर्चा की। इस अवसर पर कार्यपालक निदेशक श्री एमएस चौहान, श्री संदीप मोदी, जीएम श्रीमती नंदिनी भट्टाचार्य, एजीएम श्री मुकेश कश्यप, डीजीएम श्री अनूप सेलेट, श्रीमती अनिमा मेरी खलको, श्रीमती स्वाति तिवारी सहित बड़ी संख्या में अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन अतिरिक्त महाप्रबंधक(जनसंपर्क) श्री उमेश कुमार मिश्र ने किया।

कलेक्टर-एसपी ने ली अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण की प्रस्तावित बैठक की तैयारियों के संबंध में अधिकारियों की बैठक

सभी अधिकारी-कर्मचारी सौंपे गए दायित्वों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करना सुनिश्चित करें : कलेक्टर

जांजगीर-चांपा मुख्यमंत्री एवं अध्यक्ष अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में 07 अगस्त 2025 गुरुवार को अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण की बैठक जिले में प्रस्तावित है। कलेक्टर श्री जन्मेजय महोबे एवं पुलिस अधीक्षक श्री विजय कुमार पांडेय ने आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आवश्यक तैयारियों के संबंध में अधिकारियों की बैठक ली।

बैठक में कलेक्टर श्री महोबे ने कहा कि सभी तैयारी समय पर पूर्ण की जाए। कलेक्टर ने हेलीपैड, बेरिकेटिंग, मीटिंग से संबंधित प्रेजेंटेशन, माईक, बैठक व्यवस्था, विद्युत, पेयजल, सुरक्षा व्यवस्था, स्वच्छता, आवागमन, रोड क्लीयरेंस, प्रवेश पास आदि के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को समय सीमा में कार्य पूरा करने कहा गया। कलेक्टर ने सभी संबंधित अधिकारियों से कहा कि वे

अपने-अपने दायित्वों का निष्ठापूर्ण निर्वहन करे और यह सुनिश्चित करें कि कोई भी व्यवस्था अधूरी न रहे।

पुलिस अधीक्षक श्री पांडेय ने सुचारु ट्रैफिक नियंत्रण एवं पार्किंग व्यवस्था हेतु पुलिस विभाग को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। उन्होंने सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस बल की तैनाती, बेरिकेटिंग, एंट्री-एग्जिट पॉइंट्स एवं अन्य व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। बैठक में कमांडेंट श्री विमल बैस, जिला पंचायत सीईओ श्री गोकुल रावटे, अपर कलेक्टर श्री ज्ञानेंद्र सिंह, अपर कलेक्टर श्री आर के तंबोली सहित विभिन्न अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

जिला स्तरीय कार्यशाला का सफल आयोजन

लोकशक्ति

बिलासपुर विश्व बैंक समर्थित भारत सरकार की योजना रैम्प अंतर्गत प्रार्थना भवन खारंग जल संसाधन परिसर बिलासपुर में उद्योग एवं बैंकर्स कनेक्ट कार्यक्रम'' का आयोजन जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र बिलासपुर के तत्वाधान में आयोजित किया गया।

कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य एमएसएमई को हरित बनाने में सहायता करना ऋण तक पहुंच को सुगम बनाना बाजार तक पहुंच बनाना विलंबित भुगतान के मुद्दों का समाधान करना एवं इस संबंध में भागीदारों के साथ चर्चा परिचर्चा कर समाधान करना मुख्य उद्देश्य है। जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र बिलासपुर के मुख्य महाप्रबंधक सी.आर.टेकाम के द्वारा प्रतिभागियों को कार्यक्रम की रूपरेखा से अवगत कराते हुए नवीन उद्यम स्थापना के संबंध में औद्योगिक नीति 2024-30 के अंतर्गत प्रावधान, अनुदान, रियायतें छूट एवं अन्य सुविधाओं के संबंध में जानकारी दी गई। इस अवसर पर रैम्प योजना एवं पीएमएफएमई योजनाओं का राज्य स्तर से आये योगेश शर्मा एवं भूषण के द्वारा विस्तृत रूप से जानकारी देते हुए बैंकर्स से यथासंभव सहयोग करने का आग्रह

किया गया। कार्यशाला में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमी, पीएमएफएमई व पीएमईजीपी योजना के हितग्राही व जिले के प्रमुख बैंकों जैसे भारतीय स्टेट बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, केनरा बैंक सहित अन्य बैंकों के अधिकारियों ने भाग लेकर उपस्थित उद्यमियों को विभिन्न वित्तीय योजनाओं, ऋण सुविधाओं के लाभों की जानकारी दी गई।

कार्यक्रम का अध्यक्षता कर रहे क्षेत्रीय प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक शाखा के द्वारा अपने उद्बोधन में ऋण हेतु किये गये आवेदनों पर सकारात्मक विचार एवं सहयोग करने का आश्वासन दिया गया, प्रतिभागियों के द्वारा किये गये प्रश्नों के उत्तर से प्रतिभागी आश्वस्त हुए। इसी कड़ी में लीड बैंक अधिकारी दिनेश उरांव के द्वारा विभिन्न बैंक शाखाओं में शासकीय योजनाओं के लंबित प्रकरणों पर स्वीकृति एवं वितरित करने में विभागीय अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर लक्ष्य पूर्ति करने में कटिबद्ध होना बताया गया। सफल उद्यमी के रूप में मेसर्स रानीसती उद्योग औ.क्षे. तिफरा के इकाई स्वामी पुरूषोत्तम अग्रवाल के द्वारा अपने उद्बोधन में छोटे एवं कम लागत से उत्पादन प्रारंभ करके बड़े उद्योग तक पहुंचने में आने वाली चुनौतियों एवं उनके समाधान की जानकारी दी गयी।

कार्यक्रम में लगभग 50 प्रतिभागी शामिल हुए एवं उनके जानकारी प्राप्त करने की उत्सुकता और उत्तर प्रतिउत्तर से कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। कार्यक्रम में विभागीय अधिकारी एल.के.लाकरा महाप्रबंधक, सी.डी. प्रसाद महाप्रबंधक, संतोष धुर्वे महाप्रबंधक, सत्येंद्र वर्मा प्रबंधक, सुनील पाण्डेय प्रबंधक, ए.श्रीधर राव प्रबंधक, श्रीमती रेवती झलरिया प्रबंधक, श्रीमती आरती झलरिया प्रबंधक, एवं अन्य कर्मचारियों के साथ जिले में नियुक्त डीआरपी उपस्थित रहे।

छत्तीसगढ़ राज्य विधिज्ञ परिषद के निर्वाचन हेतु नामांकन फार्म जमा करने की प्रकिया प्रारंभ

बिलासपुर छत्तीसगढ़ राज्य विधिज्ञ परिषद के निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार आज छत्तीसगढ़ राज्य विधिज्ञ परिषद के सदस्य पद हेतु नामांकन की प्रकिया प्रारंभ हो गई है। छत्तीसगढ़ राज्य विधिज्ञ परिषद के मुख्य कार्यालय उच्च न्यायालय प्रांगण बोदरी बिलासपुर छ.ग. में सुबह 10.30 बजे से सायं 5.00 बजे तक परिषद के सदस्य के निर्वाचन हेतु नामांकन फार्म, मतदाता सूची, निर्वाचन नियमावली तथा अनापत्ति प्रमाण पत्र आदि से संबंधित कार्य प्रारंभ हुआ जिसमें पहले दिन ही कुल 54 नामांकन आवेदन पत्रों की बिकी हुई तथा आज ही दो अधिवक्ताओं कमशः प्रशांत तिवारी राजनांदगांव एवं अब्दुल वहाब खान बिलासपुर ने अपना नामांकन फार्म पूर्ण शुल्क के साथ निर्वाचन अधिकारी अमित कुमार वर्मा के समक्ष प्रस्तुत किया। परिषद के निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार दिनांक 14 अगस्त तक नामांकन फार्म जमा करने की प्रक्रिया चलेगी तथा दिनांक 16 से 23 अगस्त तक स्कूटनी तथा दिनांक 24 अगस्त से 31 अगस्त तक नामांकन फार्म की नाम वापसी की प्रक्रिया की जाएगी इसके पश्चात् दिनांक 01 सितम्बर 2025 को अंतिम उम्मीदवारों की सूची प्रकाशित की जाएगी।

खास खबर

जिले में अब तक 675.3 मि.मी. बारिश दर्ज

बिलासपुर बिलासपुर जिले में चालू खरीफ मौसम में अब तक 675.3 मि.मी. बारिश दर्ज की गई है। जो कि पिछले 10 वर्ष के औसत बारिश 545.8 मि.मी. से 129.5 मि.मी. अधिक है। अधीक्षक भू अभिलेख से प्राप्त जानकारी के अनुसार सबसे अधिक बारिश 820.4 मि.मी. बेलगहना तहसील में और सबसे कम बारिश 546.2 मि.मी. कोटा में रिकार्ड की गई है। इसी प्रकार बिलासपुर तहसील में 798.1 मि.मी., बिल्हा तहसील में 653.5 मि.मी., मस्तूरी में 660.5 मि.मी.,तखतपुर में 729.6 मि.मी., सीपत में 645.4 मि.मी., बोदरी में 609.9 मि.मी., बेलतरा में 594 मि.मी., रतनपुर में 672.3 मि.मी., सकरी में 724.8 मि.मी. और पचपेड़ी तहसील में 648.4 मि.मी. बारिश रिकार्ड की गई है। जिले की औसत वार्षिक वर्षा 1202.3 मि.मी. है।

आमागोहन में जनसमस्या निवारण शिविर

बिलासपुर (वीएनएस)। जिले में सुशासन तिहार अंतर्गत लगाये गये शिविरों में प्राप्त आवेदनों के निराकरण, मांग के संबंध में की गई कार्यवाही के साथ ही विभागीय योजनाओं के प्रचार-प्रसार के संबंध में जिला स्तरीय शिविर का आयोजन कोटा ब्लॉक के आमागोहन में 2 अगस्त को सवेरे 11 बजे से किया जाएगा। शिविर के लिए विकासखण्ड स्तर पर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कोटा को नोडल अधिकारी तथा सीईओ जनपद पंचायत, कोटा को सहायक नोडल अधिकारी बनाया गया है। कलेक्टर ने सभी विभाग प्रमुखों को निर्धारित समय में शिविर स्थल पर विभागीय जानकारी सहित उपस्थित होने के निर्देश दिए है।

फर्जी IPS ने रिपोर्टर को किया फोन, ठगी की कोशिश

कोरबा जिले में पत्रकार से ठगी की कोशिश हुई है। रिपोर्टर मनोज यादव के पास एक संदिग्ध फोन आया। कॉलर ने खुद को आईपीएस अधिकारी उदय किरण का करीबी रिश्तेदार बताया। उसने अपने को रायपुर में सीआरपीएफ का कमांडो भी बताया।

ठग ने कहा कि उसका ट्रांसफर हो गया है और वह अपना फर्नीचर और अन्य सामान बेचना चाहता है। उसने व्हाट्सएप पर फोटो और रेट भेजने की बात कही। फोन पर बात करने का आग्रह भी किया। रिपोर्टर के ज्यादा सवाल-जवाब करने पर है अलर्ट हो गया और फोन-मैसेज करना बंद कर दिया। थाने में शिकायत के बाद पुलिस ने जांच की बात कही है। वहीं, पुलिस ने ऐसे कॉल से लोगों को अलर्ट रहने को कहा है। रिपोर्टर को ठगी का एहसास होने पर जब उसने पूछा कि उदय किरण वर्तमान में कहां पदस्थ हैं, तो ठग ने केवल 'आईपीएस हैं' कहकर टाल दिया। अधिक सवालों पर उसने फोन काट दिया। ठग ने दो दिन पहले फेसबुक पर अंग्रेजी में मैसेज किया था। उसने नाम, पता और हालचाल पूछा था। दो दिन बाद मोबाइल नंबर 8302776817 से फोन आया। बाद में इस नंबर पर कॉल करने पर कोई जवाब नहीं मिला।

कलेक्टर ने तखतपुर के फिल्ड स्तर के अधिकारियों की ली बैठक

खेती-किसानी, खाद, एग्रीस्टेक पंजीयन, बीमा की समीक्षा

संवाददाता।

बिलासपुर कलेक्टर संजय अग्रवाल ने तखतपुर विकासखण्ड के सकरी स्थित वन चेतना केन्द्र में बैठक लेकर किसान कल्याण से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा की। बैठक में विकासखण्ड के मैदानी स्तर के कर्मचारी जैसे-आरएईओ, पटवारी, सहकारी समितियों के प्रबंधक एवं आपरेटर शामिल हुए। उन्होंने अगले दस दिनों में एग्रीस्टेक पोर्टल में किसानों का बचा हुआ पंजीयन कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। तखतपुर में फिलहाल 66 प्रतिशत किसानों कापंजीयन का कार्य पूर्ण हुआ है। कलेक्टर ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत बीमा कराने की तिथि 31 जुलाई से बढ़ाकर 14 अगस्त तक कर दी गई है। इस अवधि में ज्यादा से ज्यादा किसानों को बीमा करा लेने की अपील की है। उन्होंने कहा कि अत्यंत कम बीमा प्रीमियम पर हम बड़े स्तर पर नुकसान की मार झेल सकते हैं। उन्होंने

ज्यादा आमदनी के लिए बाजार की मांग के अनुरूप फसल उत्पादन करने पर जोर दिया। इस अवसर पर उप संचालक कृषि पीडी हथेश्वर, एसडीएम शिवकुमार कंवर, खाद्य अधिकारी अमृत कुजूर भी उपस्थित थे।

कलेक्टर ने एक-एक पंचायत में एग्रीस्टेक पंजीयन की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि इस बार एग्रीस्टेक पोर्टल में पंजीकृत किसानों से ही धान खरीदी का कार्य किया जायेगा। इसलिए अभी समय है। जो किसान अभी तक नहीं कराये हैं, वे स्थानीय च्वाईस सेन्टर या लोक सेवा केन्द्र में करा लें। पंजीयन की प्रक्रिया अत्यंत आसान है। अपनी जमीन का रिकार्ड, आधार कार्ड एवं मोबाइल नम्बर के साथ पंजीयन कराया जा सकता है। कलेक्टर ने बीमा कराने की बढ़ी हुई तिथि की जानकारी देकर इस समय का लाभ उठाने की अपील किसानों से की है।

उन्होंने फिल्ड के अधिकारियों को किसान कल्याण के कार्यों पर ज्यादा जोर देने के निर्देश दिए। किसानों की खुशहाली एवं समृद्धि से ही देश की प्रगति निहित है। उन्होंने कहा कि ज्यादातर किसान छोटी जोत वाले हैं। छोटे किसानों की अकेले धान की फसल से समृद्धि लाना मुश्किल हैं। इसलिए हमें फसल विविधिकरण पर जोर देना होगा। धान के कुछ रकबे को कम कर उसमें दलहल तिलहन एवं अन्य नकदी फसलों की ओर बढ़ना होगा। उन्होंने कुछ सफल उदाहरण भी गिनाए। कलेक्टर ने बैठक में जल बचाने पर ज्यादा जोर दिया। उन्होंने जल संरक्षण की इंजेक्शन वेल तकनीक सहित व्यवहार परिवर्तन की जरूरत बताई। इसे एक-दो दिन में नहीं बल्कि इसके लिए लम्बा अभियान चलाने की जरूरत है।

उन्होंने बैठक में खेती किसानी के ताजा हालात की जानकारी ली। कलेक्टर ने कहा कि किसानों की हर प्रकार की जरूरत को ध्यान में रखा जाए। समितियों अथवा निजी दुकानों में किसी भी प्रकार के खाद की किल्लत नहीं होने चाहिए। उन्होंने नैनों यूरिया एवं नैनो डीएपी के बारे में भी किसानों को जागरूक करने के निर्देश दिए।

480 अतिथि शिक्षक पद पर निकली भर्ती, रोजगार का अवसर

कोरबा जिले में शिक्षा के क्षेत्र में एक सकारात्मक बदलाव देखने को मिला। जिला प्रशासन ने खनिज संस्थान न्यास (डीएमएफ) के तहत 480 अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की है, जिससे न केवल स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर करने में मदद मिली है, बल्कि स्थानीय बेरोजगार युवाओं को रोजगार और अध्यापन का अवसर भी प्राप्त हुआ है। इस पहल का सबसे अधिक लाभ दूरस्थ क्षेत्रों के स्कूलों, जैसे पोड़ी उपरोड़ा ब्लॉक के ग्राम पचरा के शासकीय हाई स्कूल, को हुआ है, जहां अब विद्यार्थियों को सभी विषयों की नियमित पढ़ाई का लाभ मिल रहा है। इस कदम ने विद्यार्थियों, उनके अभिभावकों और शिक्षकों में नई उम्मीद जगाई है।

कोरबा शहर से लगभग 80 किलोमीटर दूर पोड़ी उपरोड़ा ब्लॉक के ग्राम पचरा, कोरबी स्थित शासकीय हाई स्कूल क्षेत्र के एक दर्जन से अधिक गांवों के लिए शिक्षा का प्रमुख केंद्र है। इस स्कूल में आसपास के गांवों से आने वाले विद्यार्थी भविष्य को संवारने की उम्मीद के साथ दाखिला लेते हैं। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से इस स्कूल में नियमित शिक्षकों की कमी एक बड़ी समस्या थी। कई विषयों के लिए विशेषज्ञ शिक्षकों की अनुपस्थिति के कारण विद्यार्थियों को अधूरी पढ़ाई से जूझना पड़ता था, जिससे न केवल उनका मनोबल प्रभावित होता था, बल्कि उनके माता-पिता भी चिंतित रहते थे।

जिला प्रशासन ने इस समस्या का समाधान खनिज संस्थान न्यास (डीएमएफ) के माध्यम से मानदेय आधारित अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति करके किया। इस पहल के तहत पचरा हाई स्कूल में अब सभी विषयों के लिए शिक्षक उपलब्ध हैं।

7 अगस्त तक मनाया जा रहा है विश्व स्तनपान सप्ताह

शिशु के लिए स्तनपान मौलिक अधिकार तथा सर्वोत्तम आहार है

कोरबा बच्चे और माताओं के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने प्रतिवर्ष की भाँति जिले में 01 अगस्त से 07 अगस्त 2025 तक ÷स्तनपान में निवेश , भविष्य में निवेश÷ थीम के साथ मनाया जा रहा है। जिसका उद्देश्य शिशुओं के स्वास्थ्य और विकास के लिए स्तनपान के महत्व को समुदाय तक पहुँचाना है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि जिले में विश्व स्तनपान सप्ताह के आयोजन हेतु समस्त विकासखण्डो को विस्तृत दिशा निर्देश पूर्व में जारी कर दिया गया है। समस्त विकासखण्डों में स्तनपान के संबंध में डिलिवरी प्वाईट, शिशु वार्ड, पोषण पुनर्वास केन्द्रो, समस्त स्वास्थ्य केन्द्रों, में पदस्थ सीएचओ, एएनएम के माध्यम से प्रसव के तुरंत एक घंटे के अंदर नवजात को स्तनपान सुनिश्चित करने के लिए तथा 6 माह तक शिशुओं को केवल स्तनपान कराने के महत्व के बारे में जागरूक किया जा रहा हे। इसके साथ ही समुदाय स्तर पर तथा व्हीएचएनडी सत्र में स्वास्थ्य कार्यकर्ता, ऑगनबाड़ी कार्यकताओं तथा मितानिनों के द्वारा बैठक लेकर स्तनपान के लाभ तथा कुपोषण से बचाव एवं रोकथाम के लिए 06 माह तक केवल माँ का दूध तथा 06 माह के उपरांत संपूरक आहार देने के बारे में जानकारी दी जा रही है। उन्होने बताया कि मां का दूध शिशु के पोषण का एक महत्तवपूर्ण स्त्रोत है जो उसे आवश्यक पोषक तत्व और एंटीबॉडी प्रदान करता है जो शिशु को डायरिया , निमोनिया एवं कुपोषण से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है यह शारीरिक और मानसिक विकास के लिए अत्यन्त आवश्यक है नवजात को जन्म के एक घंटे के भीतर स्तनपान शुरू किया जाना आवश्यक है तथा शिश को 06 माह तक केवल स्तनपान कराया जावे क्योकि माँ के दूध में शिशु के लिए आवश्यकतानुसार पानी होता है इसलिए 06 माह तक उपर से पानी देने की आवश्यकता नहीं होती ।

करंट से हाथी की मौत, खेती व वन्य जीवियों के बीच टकराव

कोरबा जिले के कुदमुरा रेंज अंतर्गत बैगामार जंगल में शुक्रवार सुबह एक दर्दनाक हादसा सामने आया, जिसमें करंट प्रवाहित तार की चपेट में आने से एक जंगली हाथी की मौत हो गई। यह घटना वन्यजीव संरक्षण के लिहाज से बेहद चिंताजनक है और ग्रामीण इलाकों में खेती व वन्यजीवों के बीच टकराव की गंभीर स्थिति को उजागर करती है। ग्रामीणों ने सुबह खेत की ओर जाते वक्त मृत हाथी को देखा, जिसके पास खेत की सीमा पर बिछा करंट प्रवाहित तार भी मिला। इसकी सूचना तत्काल वन विभाग को दी गई। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और जांच में पाया गया कि खेत के मालिक ने अपनी फसल की

सुरक्षा के लिए खुद ही खेत के चारों ओर बिजली प्रवाहित तार लगाया था। पूछताछ में किसान ने इस बात को स्वीकार किया कि करंट से हाथी की मौत हुई है और यह तार उसी ने लगाया था।

कटघोरा डीएफओ निशांत झा ने बताया कि यह मामला गंभीर वन्यजीव अपराध के रूप में दर्ज किया गया है और आरोपी किसान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि इस कार्य में और कौन-कौन शामिल था या तकनीकी सहायता प्रदान की गई थी या नहीं। बताया जा रहा है कि हाल के दिनों में जिस क्षेत्र में यह हादसा हुआ, वहां करीब 22 हाथियों का झुंड लगातार सक्रिय है और वन विभाग पहले से इनकी गतिविधियों पर नजर रखे हुए था। इस घटना के बाद पूरे इलाके में सतर्कता और निगरानी और बढ़ा दी गई है। वन विभाग ने ग्रामीणों से अपील की है कि वे खेतों की रक्षा के लिए बिजली प्रवाहित तार जैसे खतरनाक और अवैध उपायों का इस्तेमाल न करें। इसके बजाय विभाग द्वारा स्वीकृत वैकल्पिक और सुरक्षित तरीकों को अपनाएं। विभाग ने आसपास के गांवों में जागरूकता अभियान भी शुरू किया है, जिसमें लोगों को वन्यजीव सुरक्षा, सह-अस्तित्व और वैधानिक उपायों की जानकारी दी जा रही है। यह घटना छत्तीसगढ़ में मानव-वन्यजीव संघर्ष की बढ़ती समस्या का एक और चिंताजनक संकेत है। राज्य में लगातार हो रही हाथियों की मौतें वन्यजीव संरक्षण तंत्र पर सवाल खड़ा कर रही हैं।

दूर हुई शिक्षको की कमी, अतिथि शिक्षको की नियुक्ति से विद्यार्थियों में खुशी

शिक्षक के रूप में रोजगार मिलने से खुश है मानदेय में काम करने वाली अतिथि शिक्षक

कोरबा

शहर से लगभग अस्सी किलोमीटर दूर पोड़ी उपरोड़ा ब्लॉक के ग्राम पचरा के हाई स्कूल में विद्यार्थियों की कोई कमी नहीं है। आसपास के एक दर्जन से अधिक गाँव के विद्यार्थी इस विद्यालय बहुत ही उम्मीद के साथ यह सोचकर दाखिला लेते हैं कि यहाँ से पढ़कर, पास होकर आगे की पढ़ाई जारी रखेंगे। पिछले कुछ सालों से उनके गाँव के सबसे नजदीक इस विद्यालय में नियमित शिक्षको की कमी थी।

स्कूल में शिक्षकों की कमी उन्हें ही नहीं उनके माता-पिता को भी अक्सर चिंता में डालती थी। जिला प्रशासन द्वारा जिले में संचालित ऐसे विद्यालय जहाँ युक्ति युक्तकरण के पश्चात भी शिक्षको की कमी रह गई थीं उन विद्यालयों की सूची तैयार कर डीएमएफ से मानदेय के आधार पर नियुक्ति प्रदान की गई है। जिला प्रशासन की इस पहल के बाद शासकीय हाई स्कूल पचरा में अब किसी विश्य का कालखण्ड खाली नहीं जाता। दूरस्थ क्षेत्र से स्कूल आने वाले हर

विद्यार्थियों को इस विद्यालय में शिक्षको से अध्यापन व विषय ज्ञान मिलता है।

जिला प्रशासन द्वारा डीएमएफसे मानदेय के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है। इसी क्रम में पोड़ी उपरोड़ा ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम पचरा में संचालित हाई स्कूल में भी शिक्षको की कमी बनी हुई थी। कई विषयों के नियमित शिक्षक नहीं होने से यहाँ के विद्यार्थी उन विषयों की पढ़ाई अन्य शिक्षको के माध्यम से करते तो थे लेकिन उन्हें अक्सर महसूस होती थी कि काश सभी विषयों के लिए शिक्षक उपलब्ध हो। जिला प्रशासन द्वारा डीएमएफ से की गई मानदेय शिक्षको की नियुक्ति से जहाँ विद्यार्थियों को शिक्षक मिल गए, वहीं गाँव के आसपास रहने वाले बेरोजगार युवाओं को रोजगार के साथ अध्यापन का अवसर भी मिल गया है। पचरा के हाई स्कूल में मानदेय शिक्षक के रुप में अध्यापन कराने वाली शिक्षिका अभिलाषा सिंह तंवर और लक्ष्मी कुमारी ने बताया कि मास्टर डिग्री लेने के बाद उन्होंने बीएड किया ताकि स्कूल में पढ़ाई करा सके। जिले में मानदेय शिक्षक की भर्ती होने पर उन्होंने अपना आवेदन किया था, अब नियुक्ति होने के बाद वह स्कूल में पढ़ाती है। उन्होंने बताया कि मानदेय शिक्षक के रूप में स्कूल में अवसर मिलना उनके लिए सौभाग्य का विषय है। मानदेय मिलने से घर का खर्च चलाने में सहूलियत होने लगी है। उन्होंने बताया कि विद्यार्थियों को भी खुशी होती है कि उनका कोई भी विषय खाली नहीं जाता। इस विद्यालय में कक्षा नवमीं में 48 और कक्षा 10वीं में 25 विद्यार्थी है। विद्यालय में गणित, अंग्रेजी और विज्ञान के शिक्षक है।

शिक्षिकाओं द्वारा हिंदी,सामाजिक विज्ञान और अन्य विषयों की पढ़ाई कराई जाती है। विद्यालय में अध्ययन करने वाली छात्राओं विद्या, मानमती, सुहानी यादव ने बताया कि पहले विद्यालय में कम शिक्षक थे। अब नए शिक्षको के आने से सभी विषयों की पढ़ाई होती है। विद्यार्थियों ने बताया कि इस स्कूल में बहुत दूर-दूर के गाँव से लड़के-लड़कियां पढ़ाई करने आती है। सभी विषयों की पढ़ाई होने से हम लोग का मन भी स्कूल आने में होता है।

आर्थिक तंगी और मानसिक तनाव से जूझ रहे पेंटर ने की आत्महत्या

कोरबा)। मानिकपुर चौकी क्षेत्र में एक दर्दनाक घटना में 45 वर्षीय पेंटर राकेश चौहान ने अपने घर में लोहे के एंगल से साड़ी के सहारे फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। गुरुवार रात खाना खाने के बाद वह अपने कमरे में सोने गया था। शुक्रवार सुबह परिजनों ने जब उसका कमरा खोला तो वह पंखे पर लटका मिला।

स्थानीय भाजपा नेता सरजू द्वारा पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद मानिकपुर चौकी प्रभारी सुदामा पाटले की टीम मौके पर पहुंची और मर्ग कायम कर जांच शुरू की। परिजनों के बयान के अनुसार, राकेश की पत्नी 12 साल पहले उसे छोड़कर दूसरी शादी कर चुकी थी। तब से राकेश अकेले अपनी बेटी की परवरिश कर रहा था, जो वर्तमान में कक्षा नौवीं में पढ़ती है।

बताया गया कि राकेश शहर का जाना-पहचाना पेंटर था और वर्षों से इसी पेशे में सक्रिय था। लेकिन आर्थिक हालात कमजोर होने के कारण वह मानसिक तनाव में रहने लगा था। बीमारी के बावजूद इलाज कराने में असमर्थ था।

पुलिस आत्महत्या के कारणों की गहराई से जांच कर रही है। यह घटना न केवल आर्थिक संकट की मार झेल रहे लोगों की व्यथा को उजागर करती है, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता की जरूरत को भी रेखांकित करती है।

जामुल में श्रीराम कथा का आयोजन एक जनवरी 2026 को

भिलाई । छत्तीसगढ़ के जामुल में आयोजित होने वाली श्रीराम कथा महोत्सव (सनातन उत्सव), में परमपूज्य आचार्य श्रीयुत पं. युवराज पाण्डेय जी महाराज 1 जनवरी 2026, गुरुवार को होंगे शामिल। छत्तीसगढ़ के जामुल नगर में पूज्यपाद अनंतश्रीविभूषित श्रीधाममठाधीश्वर जगतगुरु रामानुजाचार्य डॉ. स्वामी श्री राघवाचार्य जी महाराज(श्री रामलला जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, अयोध्या धाम) के अमृतवर्षीणी वाणी से 28 दिसम्बर 2025 से 06 जनवरी 2026 तक शिवपुरी- स्टेडियम, जामुल,जिला - दुर्ग (छत्तीसगढ़) में आयोजित होने वाली श्रीराम कथा महोत्सव (सनातन उत्सव) में आयोजन समिति के आमंत्रण को स्वीकार करते हुए परमपूज्य आचार्य श्रीयुत पं. युवराज पाण्डेय जी महाराज 1 जनवरी 2026, गुरुवार को दोपहर 2:00 बजे अपनी गरिमामय उपस्थिति प्रदान करेंगे। श्रीराम कथा महोत्सव (सनातन उत्सव)

यूनिहोम्स कॉलोनी में बच्चों की भव्य चित्रकला प्रदर्शनी

रायपुर । राजधानी रायपुर के भाठागाँव स्थित यूनिहोम्स कॉलोनी में आज रविवार 3अगस्त को बच्चों की चित्रकला प्रदर्शनी आयोजित की गयी. कॉलोनी के यूनिक्लब में यह आयोजन डी.आर्ट क्लासेज के तत्वावधान में किया गया.संस्था की कला-शिक्षिका श्रीमती दीपा पटेल और उनके विद्यार्थियों ने इसमें हिस्सा लिया. प्रदर्शनी में विशेष रूप से पाँच वर्ष से पंद्रह वर्ष आयु समूह के बच्चों द्वारा निर्मित रंग -बिरंगे कलात्मक चित्र रखे गए थे, जो प्रकृति और प्रवृत्ति , धर्म और संस्कृति तथा इतिहास से संबंधित थे. इस कार्यक्रम में बच्चों के साथ उनके अभिभावकों ने भी हिस्सा लिया.वरिष्ठ साहित्यकार एवं पर्यावरणविद् डॉ.माणिक विश्वकर्मा 'नवरंग' ने भी प्रदर्शनी स्थल पहुँचकर बच्चों का उत्साह बढ़ाया.उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजनों से कॉलोनी के बच्चों में चित्रकला एवं भारतीय संस्कृति के प्रति रूझान जागृत होगा।

मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय की पहल पर ग्राम जोरंडाझरिया के निमटोली में पुनः बहाल हुई विद्युत आपूर्ति

ग्रामीणों ने जताया मुख्यमंत्री के प्रति आभार

जशपुरनगर । मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय की पहल पर फरसाबहार, ग्राम जोरंडाझरिया के निमटोली बस्ती में खराब ट्रांसफार्मर के कारण ठप पड़ी बिजली आपूर्ति पुनः बहाल हो गई है। बिजली संकट झेल रहे ग्रामीणों को इससे बड़ी राहत मिली है। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की है।

उल्लेखनीय है कि तहसील फरसाबहार, ग्राम जोरंडाझरिया के निमटोली बस्ती के ग्रामीणों ने कैंप कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत कर बताया कि ट्रांसफार्मर खराब होने की वजह से बिजली की आपूर्ति बाधित है। इससे उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बरसात के दिनों में विषैले जीवों का खतरा भी बना रहता है। कैंप कार्यालय ने मामले को गंभीरता से लेते हुए त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की, जिसके तहत विद्युत विभाग द्वारा निमटोली बस्ती में ट्रांसफार्मर बदल दिया गया। इससे बिजली आपूर्ति सुचारू रूप से बहाल हो गई है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय द्वारा बगिया में स्थापित मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में जनसमस्याओं का तत्परता के साथ समाधान किया जाता है। विशेषकर बिजली, पानी और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी आवश्यकताओं से संबंधित समस्याओं पर प्राथमिकता से कार्रवाई की जा रही है।

पशु चिकित्सा विभाग में 15 पदों पर भर्ती, 11 अगस्त तक कर सकते हैं आवेदन

बस्तर । जिले के पशु चिकित्सा विभाग में सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी (तृतीय श्रेणी) के 15 रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस संबंध में संयुक्त संचालक, पशु चिकित्सा सेवाएं कार्यालय द्वारा आधिकारिक विज्ञापन जारी किया गया है। भर्ती संविदा आधार पर एक वर्ष के लिए की जाएगी, जिसमें चयनित अभ्यर्थियों को प्रतिमाह 18,000 का मानदेय प्रदान किया जाएगा। इच्छुक उम्मीदवारों को अपने मूल दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रतियों सहित आवेदन पत्र कार्यालय में जमा करना होगा। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 11 अगस्त 2025, शाम 5 बजे निर्धारित की गई है। तय समय के बाद आने वाले आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इन पदों के लिए आवेदन करते समय कुछ शर्तें भी रखी गई हैं जैसे कृत्रिम गर्भाधान में दक्ष अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके साथ ही बस्तर जिले के मूल निवासियों को भी वरीयता दी जाएगी। चयन प्रक्रिया में शैक्षणिक योग्यता और अनुभव को आधार बनाया जाएगा। सेवा अवधि के दौरान मानदेय में किसी प्रकार की कटौती नहीं की जाएगी। इस भर्ती से जुड़ी अधिक जानकारी बस्तर जिले की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है।

हनुमान नगर में डेढ़ दिनों से नलों में पानी नहीं, रहवासी हो रहे परेशान

रायपुर, 03 अगस्त (आरएनएस)। नगर निगम जोन क्रमांक 5 के अंतर्गत आने वाले हनुमान, चंद्रशेखर नगर एवं अन्य आसपास के क्षेत्रों में गत डेढ़ दिनों से नलों में पानी नहीं आने से जल संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है। नगर निगम के जिम्मेदारों द्वारा इस संबंध में रहवासियों को किसी भी प्रकार के सुधार कार्य की जानकारी नहीं दी गई है जिसके चलते रहवासी पानी नहीं मिलने से परेशान है। इस संबंध में रहवासियों ने वार्ड पार्षद एवं जोन आयुक्त से तत्काल पानी बहाली की मांग की है। महापौर ने गत दिनों एमआईसी की बैठक में कहा था कि शहर के 70 वार्डों में किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न होने पर तत्काल समस्या का निदान किया जाएगा किंतु डेढ़ दिनों बाद भी नगर निगम कर्मचारियों द्वारा जलापूर्ति बहाल नहीं की गई है रहवासियों ने महापौर से भी जल व्यवस्था बिना किसी पूर्व सूचना के अवरोध उत्पन्न करने पर संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

सावन की पावन बेला में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने किया भगवान शिव का रुद्राभिषेक

सावन की पावन बेला में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने किया भगवान शिव का रुद्राभिषेक

भक्ति, संस्कृति और समरसता का संगमः रायपुर की भव्य कांवड़ यात्रा में शामिल हुए मुख्यमंत्री

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय सावन मास के पवित्र अवसर पर राजधानी रायपुर के गुढ़ियारी क्षेत्र में आयोजित विशाल कांवड़ यात्रा में शामिल हुए। उन्होंने भगवान भोलेनाथ का रूद्राभिषेक कर छत्तीसगढ़ प्रदेश की खुशहाली, समृद्धि और जनकल्याण की कामना की।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि आज मारूति मंगलम भवन, गुढ़ियारी से हटकेश्वरनाथ महादेव मंदिर तक हजारों की संख्या में कांवड़िए जलाभिषेक हेतु रवाना हुए हैं। उन्होंने कहा कि यह आयोजन छत्तीसगढ़ की गौरवशाली सांस्कृतिक परंपरा को जीवंत बनाए रखने का कार्य करता है और हमारे लोक-विश्वास की गहराई को प्रकट करता है। सावन महीने में कांवड़ यात्रा शिवभक्तों की आस्था, भक्ति और समर्पण का प्रतीक है, जिसमें श्रद्धालु कई-कई किलोमीटर पदयात्रा कर भोलेनाथ को जल अर्पित करते हैं।मुख्यमंत्री ने कहा कि रायपुर के महादेव घाट स्थित भगवान हटकेश्वरनाथ महादेव का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व अत्यंत गहरा है। यहां श्रद्धालु बड़ी संख्या में जलाभिषेक हेतु एकत्र होते हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की धरती भक्ति, श्रद्धा और संस्कृति का अद्वितीय संगम है। कांवड़ यात्रा जैसी आयोजन न केवल परंपरा को सहेजते हैं, बल्कि आध्यात्मिक चेतना और सामाजिक समरसता का भी संदेश देते हैं। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह, पूर्व राज्यपाल श्री रमेश बैस, कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी रजवाड़े, लोकसभा सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल, रायपुर पश्चिम विधायक श्री राजेश मूणत, रायपुर दक्षिण विधायक श्री सुनील सोनी, रायपुर ग्रामीण विधायक श्री मोतीलाल साहू, रायपुर उत्तर विधायक श्री पुरंदर मिश्रा, पूर्व सांसद श्री अभिषेक सिंह और रायपुर महापौर श्रीमती मीनल चौबे सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु, गणमान्य नागरिक एवं सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

मोबाइल छीनकर भागने वाले दो आरोपी गिरफ्तार

रायपुर । थाना उरला पुलिस ने मोबाइल झपटमारी की घटना को अंजाम देकर फरार हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपियों के कब्जे से वीवो कंपनी का एक मोबाइल जिसकी कीमत लगभग 30,000 है, एवं घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल स्प्लेंडर को भी जब्त किया गया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, प्रार्थी ने थाना उरला में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि दिनांक 30 जुलाई 2025 को शाम लगभग 6 बजे वह सटरन फेरोलाईस प्रा. लि. कंपनी, उरला से पैदल घर जा रहा था। रास्ते में उसने अपने दोस्त राहुल को कॉल करने के लिए जैसे ही जेब से फोन निकाला, तभी मोटरसाइकिल सवार दो अज्ञात युवकों में से पीछे बैठे युवक ने उसका मोबाइल झपट लिया और दोनों तेजी से भाग निकले। प्रार्थी ने उनका पीछा करने की कोशिश की, लेकिन वे फरार हो गए। झपटा गया मोबाइल वीवो कंपनी का था, जिसमें छत्तीश का सिम (मोबाइल नंबर 7909365575) लगा हुआ था और जिसकी कीमत करीब ?30,000 बताई गई। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद थाना उरला की एंटी क्राइम एवं साइबर यूनिट की टीम ने घटना स्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन कर तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर दो संदिग्ध व्यक्तियों मनोज ताखर एवं तोमेश वर्मा की पहचान की। पूछताछ में दोनों ने अपराध करना स्वीकार किया।

तिरिया में प्राकृतिक पर्यटन और आजीविका संवर्धन का नया मॉडल,

रायपुर। बस्तर जिला मुख्यालय जगदलपुर से लगे ग्राम तिरिया ने सामुदायिक प्रयासों के माध्यम से प्राकृतिक पर्यटन एवं आजीविका संवर्धन का अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया है। वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत सामुदायिक वन संसाधनों पर अधिकार प्राप्त होने के पश्चात् ग्राम सभा तिरिया द्वारा पर्यावरण संरक्षण तथा ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में निरंतर कार्य किया जा रहा है। इसी क्रम में बीते 27 जुलाई को ग्राम सभा एवं सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन समिति के संयुक्त तत्वावधान में तिरिया संगम पिकनिक स्पॉट में व्यापक पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह प्राकृतिक पर्यटन स्थल ग्राम सभा द्वारा संचालित है, जहाँ ग्रामीणों द्वारा पर्यटकों के लिए बाँस से निर्मित नौका (बैम्बू राफ्टिंग) एवं पिकनिक जैसी सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाती हैं।वन अधिकार पत्र प्राप्त होने से पूर्व भी ग्रामवासी जंगल की सुरक्षा हेतु 23-23 सदस्यों की गश्ती टीमों का गठन कर सक्रिय रहते थे, किन्तु इससे ग्रामीणों को स्थायी आय का साधन उपलब्ध नहीं हो पा रहा था। ऐसी स्थिति में ग्राम सभा की बैठक में सर्वसम्मति से तिरिया संगम को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार के

अवसरों का सृजन करना था।पिछले दो वर्षों से पर्यटकों से संग्रहित शुल्क का उपयोग वर्ष 2025 में आम, जामुन, आँवला, बेर, नारियल, बादाम, कचनार, बांस, कदम्ब, नीम एवं विभिन्न फूल तथा औषधीय पौधों सहित मिश्रित प्रजातियों के पौधे क्रय एवं रोपण हेतु किया गया। यह पौधरोपण केवल पर्यटन स्थल तक सीमित न रहकर नालों के किनारे-किनारे भी किया गया है। इससे आगामी वर्षों में हरित आवरण में वृद्धि के साथ-साथ फलों एवं औषधीय पौधों के माध्यम से अतिरिक्त आय उपलब्ध होने की संभावना है। ग्राम सभा की इस अभिनव पहल की प्रशंसा करते हुए वन विभाग द्वारा भी विभिन्न प्रकार के पौधे प्रदान किए गए, जिनका रोपण उसी पर्यटन परिसर में ग्रामवासियों द्वारा किया गया।ग्राम तिरिया का यह सामुदायिक प्रयास न केवल पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है, बल्कि इस बात का सशक्त प्रमाण भी है कि जब स्थानीय समुदायों को अधिकार एवं संसाधन प्रदान किए जाते हैं, तो वे क्षेत्रीय विकास तथा प्राकृतिक धरोहरों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। यह मॉडल निश्चित रूप से अन्य ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अनुकरणीय है।

पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने सुप्रीम कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी दी

रायपुर। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हुए गिरफ्तारी से राहत की मांग की है। शराब घोटाला, कोयला घोटाला और महादेव सट्टा ऐप जैसे मामलों में नाम आने के बाद बघेल ने अग्रिम जमानत याचिका दायर की है। उन्होंने केंद्रीय जांच एजेंसियों सीबीआई और ईडी की कार्यप्रणाली और अधिकार क्षेत्र को भी चुनौती दी है।

भूपेश बघेल का कहना है कि उन्हें राजनीतिक बदले की भावना से निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने आशंका जताई कि जिस तरह उनके बेटे चैतन्य बघेल को गिरफ्तार किया गया, उसी तरह उन्हें भी फंसाया जा सकता है। बघेल ने यह भी मांग की है कि उन्हें जांच में सहयोग करने का मौका दिया जाए, लेकिन बिना गिरफ्तारी के। इसी मामले में उनके बेटे चैतन्य बघेल की जमानत याचिका पर भी सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। चैतन्य ने अपनी याचिका में कहा है कि श्वष्ठ की एफ्आईआर में न तो उनका नाम है और न ही किसी बयान में उनका जिक्र किया गया है। इसके बावजूद उन्हें हिरासत में लिया गया, जो कि राजनीतिक उद्देश्य से की गई कार्रवाई है। वर्तमान में चैतन्य न्यायिक हिरासत में हैं।

प्रधानमंत्री जनमन योजना से बुचूराम को मिला पक्का आशियाना

प्रधानमंत्री जनमन योजना से बुचूराम को मिला पक्का आशियाना

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत जरूरतमंद एवं कमजोर वर्ग के परिवारों को सुरक्षित आवास एवं मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध कराने की दिशा में निरंतर प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम में जशपुर जिले के बगीचा विकासखण्ड अंतर्गत ग्राम पंचायत पंडरापाठ निवासी श्री बुचूराम को प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत पक्का आवास प्रदान किया गया है।

श्री बुचूराम लकड़ी और पैरा से निर्मित कच्चे घर में परिवार सहित निवास करते थे, जहाँ वर्षा, धूप एवं जीव-जंतुओं से उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। दैनिक मजदूरी कर जीवनयापन करने वाले श्री बुचूराम आर्थिक रूप से इतने सक्षम नहीं थे कि स्वयं पक्का मकान बनवा सकें। प्रधानमंत्री जनमन योजना उनके लिए आशा की किरण बनकर आई, जिसके अंतर्गत उन्हें सुरक्षित, स्थायी एवं पक्का आवास उपलब्ध कराया गया।

श्री बुचूराम ने बताया कि अब उनके पास प्रधानमंत्री जनमन योजना के आवास के साथ-साथ आधार कार्ड, राशन कार्ड एवं आयुष्मान कार्ड जैसी महत्वपूर्ण सुविधाएँ भी उपलब्ध हैं, जिनकी सहायता से वे शासकीय योजनाओं का नियमित लाभ प्राप्त कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पक्का मकान मिलने से अब उनका परिवार सुरक्षित एवं सम्मानजनक जीवन जी रहा है।

उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति वर्ग के परिवारों को प्रधानमंत्री जनमन योजना के माध्यम से आवासीय सुविधा के साथ-साथ स्वास्थ्य, राशन एवं अन्य मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। इससे ऐसे परिवारों को मुख्यधारा से जोड़कर उन्हें सामाजिक एवं आर्थिक रूप से सक्षम बनाया जा रहा है।

पीएम किसान सम्मान निधि योजना से उमेश नंदराम की खेती को मिला आर्थिक संबल

जशपुर। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से देशभर के करोड़ों किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। इसी क्रम में जशपुर विकासखंड के ग्राम सालहेकेराडीह निवासी श्री उमेश नंदराम को भी हाल ही में योजना की 20वीं किस्त की राशि प्राप्त हुई है।

श्री नंदराम ने बताया कि वे विगत कई वर्षों से इस योजना के लाभार्थी हैं और प्रत्येक किस्त से उन्हें अपनी खेती किसानी में निरंतर सहयोग मिल रहा है। उन्होंने कहा, ÷इस बार मिली किस्त की राशि का उपयोग मैं खाद-बीज की खरीद और खेत की मजदूरी देने में कर रहा हूँ। यह सहायता समय पर मिलती है जिससे कृषि कार्यों में व्यवधान नहीं आता।

उन्होंने इस योजना के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह योजना किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। इससे खेती के लिए जरूरी संसाधन जुटाने में मदद मिलती है और आर्थिक संकट से राहत मिलती है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत प्रत्येक पात्र किसान परिवार को वर्ष में ?6,000 की सहायता राशि तीन समान किस्तों में दी जाती है, जिससे उन्हें खेती संबंधी कार्यों में सहूलियत होती है।

स्वामी,मुद्रक,प्रकाशक प्रेमेन्द्र अग्रवाल द्वारा अस्मा पब्लिशर्स इण्डिया प्राईवेट लि.,जयस्तंभ चौक, रायपुर से मुद्रित कर तथा 5/756 रामसागरपारा, सिंधी स्कूल के पीछे, स्टेशनरी हाऊस, रायपुर 492001 (छ.ग.) से प्रकाशित। संपादक प्रेमेन्द्र अग्रवाल ।
www.lokshakti.in, lokshaktidaily@gmail.com, twitter.com/lokshaktidaily, facebook.com/lokshaktidaily कार्यकारी संपादक : राजेश अग्रवाल (किसी भी विवाद पर न्यायालय क्षेत्र रायपुर होगा)